आर्थिक मध्यस्थता:

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

I. पृष्ठभूमि

A. एनसीआरपीबी के बारे में

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), का गठन 1985 में एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत हुआ था, जो शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। एनसीआरपीबी के पास भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का अधिकार है। एनसीआर 33,578 वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) के क्षेत्र में फैला हुआ है। एनसीआरपीबी के कार्यों में से एक यह है कि वह केंद्रीय और राज्य योजना कोष और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से एनसीआर में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करे और उसकी निगरानी करे।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली (एनसीआर क्षेत्र का 4.4 प्रतिशत); हरियाणा उप-क्षेत्र - हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात और पानीपत जिले (एनसीआर क्षेत्र का 40.0 प्रतिशत); राजस्थान उप-क्षेत्र - राजस्थान का अलवर जिला (एनसीआर क्षेत्र का 23.3 प्रतिशत); उत्तर प्रदेश (यूपी) उप-क्षेत्र - यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत जिले (एनसीआर क्षेत्र का 32.3 प्रतिशत) हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, एनसीआर की कुल जनसंख्या 37.1 मिलियन है, जिसका औसत कुल घनत्व 1,104 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

3. एनसीआर के अलावा, एनसीआरपीबी ने संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से निम्नलिखित काउंटर मैग्नेट एरिया (सीएमए) की भी पहचान की, जो: (i) ग्वालियर (मध्य प्रदेश); (ii) पटियाला (पंजाब); (iii) अंबाला और हिसार (हरियाणा); (iv) कोटा (राजस्थान); (v) कानपुर और बरेली (यूपी); तथा (vi) देहरादून (उत्तराखंड) हैं। क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विकास कार्यक्रमों को लागू करने हेतु इनकी स्थिति, जनसंख्या और संभावित वृद्धि पर विचार करते हुए इनकी पहचान की गई थी।

B. एनसीआरपीबी के कार्य

4. एनसीआरपीबी अधिनियम, 1985 बोर्ड के विभिन्न कार्यों को निर्धारित करता है, जैसे: (i) क्षेत्रीय और कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना; (ii) प्रतिभागी राज्यों और एनसीटी की उप-क्षेत्रीय और परियोजना योजनाओं की तैयारी की व्यवस्था करना; (iii) प्रतिभागी राज्यों और एनसीटी के माध्यम से क्षेत्रीय, कार्यात्मक, उप-क्षेत्रीय और परियोजना योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना; (iv) परियोजना निर्माण में प्रतिभागी राज्यों और एनसीटी द्वारा उचित और व्यवस्थित प्रोग्रामिंग सुनिश्चित करना, एनसीआर या उप-क्षेत्रों में प्राथमिकताओं का निर्धारण और क्षेत्रीय योजना में बताए गए चरणों के अनुसार एनसीआर के विकास को चरणबद्ध करना और (v) केंद्रीय और राज्य योजना निधि और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से एनसीआर में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना और उसकी निगरानी करना।

C. एनसीआरपीबी परियोजना वित्तपोषण

1. पृष्ठभूमि

5. जैसा कि पिछले सेक्शन में चर्चा की गई है, एनसीआरपीबी के कार्यों में से एक केंद्रीय और राज्य योजना निधि और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से एनसीआर में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना और उसकी देखरेख करना है। इस उद्देश्य के लिए एनसीआरपीबी फंड बनाया गया है।

---

[1] यह 27o03'-29o29' उत्तरी अक्षांश और 76o07'-78o29' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।.

एनसीआरपीबी एनसीआर और सीएमए में कार्यान्वित विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकता है जिनकी पहचान एनसीआरपीबी, प्रतिभागी राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), विकास प्राधिकरणों (डीए), आवास बोर्डों, औद्योगिक विकास निगमों या राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। एनसीआरपीबी एक उप-परियोजना के लिए अनुमानित लागत के 75% तक ऋण प्रदान करता है और बाकी राज्य सरकार और उनकी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा योगदान करने की जरुरत होती है। निम्नलिखित आंकड़ा एक पाई-चार्ट प्रदान करता है जो आज तक के परियोजना प्रकार (संख्या या मूल्य के आधार पर) के ब्रेकडाउन को दर्शाता है।

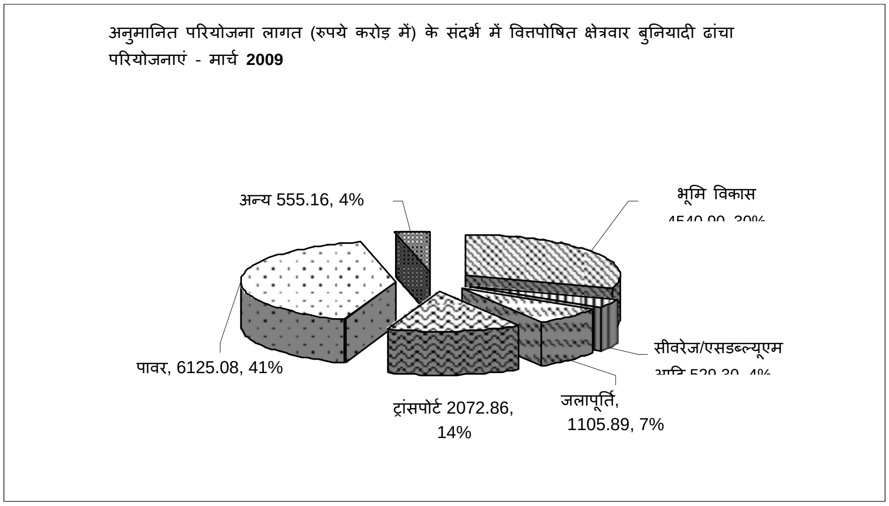

6. एनसीआरपीबी एनसीआर और सीएमए में प्रतिभागी राज्य सरकारों, यूएलबी और अन्य आईए को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। मार्च 2009 तक, एनसीआरपीबी ने लगभग 150 बिलियन रुपये की कुल लागत के साथ 230 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया, जिनमे से 111 पूरी हो चुकी हैं और 119 चल रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण की कुल राशि लगभग 60 अरब रुपये है, जिसमें से मार्च 2009 तक 40.5 अरब रुपये का वितरण हो चुका है।

2. परियोजनाओं के प्रकार

7. एनसीआरपीबी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण में शामिल है। यह एक योजना एजेंसी भी है। एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में विविध प्रकार की नियोजन भागीदारी होती है। निम्न तालिका उन परियोजनाओं के प्रकारों की सूची प्रदान करती है जिन्हें एनसीआरपीबी संभवतः फाइनेंस कर सकता है।

तालिका 1: वे परियोजनाएं जिन्हे एनसीआरपीबी फाइनेंस कर सकता है

क्र.सं.	परियोजनाओं के प्रकार
1	राजमार्ग
2	बिजली उत्पादन
3	ट्रांसमिशन और वितरण
4	क्षेत्रीय विकास-दिल्ली-मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर और अन्य क्षेत्रीय पहलें: बुनियादी ढांचा; सामान्य औद्योगिक - अवसंरचना; और लॉजिस्टिक्स हब
5	जल संसाधन/संरक्षण
6	अपशिष्ट जल प्रबंधन-घरेलू
7	अपशिष्ट जल प्रबंधन-औद्योगिक: संचय; स्थानांतरण; उपचार; और निपटान
8	जल आपूर्ति: स्रोत विकास; संचरण; और वितरण
9	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: संचय; स्थानांतरण; उपचार; और निपटान
10	अन्य नगरपालिका सेवाएं

क्र.सं.	परियोजनाओं के प्रकार
11	शहरी परिवहन: नेटवर्क-सड़कें, फुटपाथ और प्रकाश व्यवस्था; सिग्नलिंग; क्षेत्र यातायात नियंत्रण; ब्रिज और सड़क के ऊपर ब्रिज; टर्मिनल-ट्रक, बस, मल्टी मॉडल; पार्किंग; और मेट्रो/रेलवे के विशिष्ट घटक
12	सूचना प्रौद्योगिकी: नेटवर्क-वैन और लैन; हार्डवेयर; और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन

3. परियोजना चक्र

8. नीचे दिया गया फ्लो चार्ट मूल परियोजना चक्र को दर्शाता है जिसका पालन एनसीआरपीबी अपनी ऋण प्रक्रिया के लिए करता है।

फ्लो चार्ट: एनसीआरपीबी मूल परियोजना चक्र

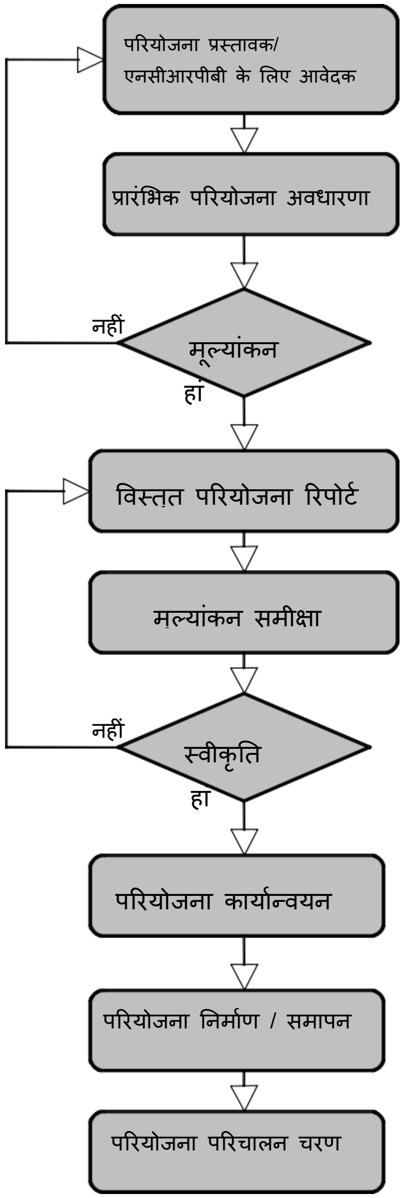

D. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस)

1. मौजूदा ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियाएं

a. पर्यावरण

9. वर्तमान में, एनसीआरपीबी अपनी तकनीकी ड्यू डिलिजेंस के साथ-साथ आकस्मिक रूप में पर्यावरणीय ड्यू डिलिजेंस भी करता है। जब परियोजना प्रस्तावक/आईए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ ऋण के लिए अनुरोध करता है, तो एनसीआरपीबी मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त एजेंसी (राष्ट्रीय संस्थान [एनआई]) को नियुक्त करता है और डीपीआर को समीक्षा के लिए एनआई को भेजता है।

10. एनसीआरपीबी ने इन एनआई के साथ निरंतर आधार पर मूल्यांकन करने के लिए एक समझौता किया है। इन समझौतों के एक भाग के रूप में, मूल्यांकन एजेंसी के पालन के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) हैं। इस टीओआर में पर्यावरण संबंधी ड्यू डिलिजेंस शामिल है। हालांकि, मूल्यांकन एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना के लिए एक सीमित बजट दिया जाता है, केवल यह निर्धारित करने के लिए सत्यापन किया जाता है कि अगर आवश्यक है तो पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की गई है या नहीं। मूल्यांकन एजेंसियों के पास यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता होती है कि परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं। चूंकि यह मंजूरी तक ही सीमित है, मूल्यांकन एजेंसियां स्पष्ट जांच या सत्यापन नहीं करती हैं कि सरकारी वर्गीकरण सही ढंग से किया गया है या नहीं। अगर इन्हें प्राप्त किया जाता है, तो मूल्यांकन एजेंसी ऋण प्रसंविदा के रूप में निकासी की शर्तों का अनुपालन शामिल करती है। अगर ये प्राप्त नहीं होते हैं, तो मूल्यांकन एजेंसी एनसीआरपीबी को सिफारिश करती है कि आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना संवितरण की शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा। एनसीआरपीबी यह पुष्टि करने के बाद ही भुगतान करता है कि ये मंजूरी प्राप्त हो गई है। सरकार की नीति में, वित्तीय संस्थानों पर पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली या पर्यावरण ढांचे जैसी कोई विशिष्ट पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है। इसलिए, एनसीआरपीबी की पर्यावरण मंजूरी की जांच अच्छे कार्य के लिए की जाती है न कि कानूनी आवश्यकता के रूप में।

11. हालांकि एनसीआरपीबी के पास मूल्यांकन में सहायता करने के लिए एनआई हैं, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए ऐसी कोई सहायता एजेंसियों की योजना नहीं है। इसलिए, मौजूदा प्रक्रियाओं में, पर्यावरण मंजूरी की शर्तों और/या अच्छे पर्यावरणीय कार्यों का पालन किया जाता है या नहीं, इसकी कोई जांच नहीं है।

12. संक्षेप में, एनसीआरपीबी मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पर्यावरणीय ड्यू डिलिजेंस आरंभ करता है, लेकिन यह पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने वाली परियोजना के दस्तावेजी साक्ष्य को सत्यापित करने तक सीमित है। और, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन या अच्छे पर्यावरणीय कार्यों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए कोई पर्यवेक्षण नहीं है।

13. सरकार और डोनर नीति (जैसे एशियाई विकास बैंक [एडीबी] और विश्व बैंक) की तुलना में, यह देखा जा सकता है कि दोनों नीतियों में स्क्रीनिंग, वर्गीकरण, पर्यावरण मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) कार्यान्वयन है। हालाँकि, दो नीतिगत आवश्यकताओं में भिन्नताएँ हैं, जैसे मामूली उत्क्रमणीय प्रभावों वाली कुछ परियोजनाओं के लिए, सरकारी नीति के लिए एक प्रश्नावली को पूरा करने की आवश्यकता होती है जबकि डोनर, जैसे एडीबी को प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षण (आईईई) की आवश्यकता होती है। एनसीआरपीबी के ईएसएमएस को दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, सरकारी नीति के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी नहीं की जाती है, जबकि डोनर नीति के कार्यान्वयन में आवधिक निगरानी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। सरकारी नीति की तुलना में डोनर नीति में कार्यान्वयन पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और एक व्यापक अर्थ में, डोनर नीति के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास ईएसएमएस होना आवश्यक है, जबकि सरकारी नीति में ऐसा नहीं है। इसलिए, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक बुनियादी प्रणाली के संदर्भ में एनसीआरपीबी के पास जो पहले से मौजूद है, उसे ईएसएमएस आगे संरचित और व्यवस्थित करेगा।

b. सामाजिक

14. सामाजिक मुद्दों के लिए, परियोजना प्रस्तावकों/आईए द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विभिन्न परियोजना घटकों के लिए आवश्यक भूमि का निम्नलिखित विवरण प्रदान करते हैं: जैसे आवश्यक सीमा, जिस उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है, भूमि का प्रकार, चाहे निजी या सरकारी और निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए किए गए बजटीय प्रावधान।

15. हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इसमें अनैच्छिक विस्थापन और/या स्थानीय लोगों (आईपी) पर प्रभाव शामिल है, भूमि उपयोग और भूस्वामियों के प्रोफाइल पर विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहां सरकारी जमीन उपलब्ध बताई जाती है, वहां कोई अतिक्रमण है या नहीं या यह अतिक्रमण से मुक्त है, इसकी जानकारी नहीं है।

16. मूल्यांकन करने के लिए एनआई को टीओआर में सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं जिन्हें अनुपालन के लिए सत्यापित करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मूल्यांकन को उनके सामाजिक प्रभावों और उनके न्यूनीकरण के उपायों के लिए डीपीआर की समीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा, समीक्षा में गरीबों और कमजोर लोगों के लिए सेवाओं के प्रावधानों पर ध्यान देना होगा, जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता भी शामिल है। चूंकि, डीपीआर में परियोजना में अनैच्छिक पुनर्वास (आईआर) या आईपी शामिल है या नहीं, इसकी जानकारी न तो सामाजिक प्रभावों के लिए डीपीआर की समीक्षा करती है और न ही अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में इस अंतर को इंगित करती है।

17. सामाजिक सुरक्षा नीति और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी की अनुपस्थिति और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा मुद्दों को बताने की आवश्यकता की कमी एनसीआरपीबी में सामाजिक मुद्दों को नहीं बताना मुख्य कारण है।

18. आगे, चूंकि परियोजनाओं के लिए फाइनेंस प्राप्त करने में आईआर मुद्दों को बताना अनिवार्य नहीं है, एनसीआरपीबी सहायता के साथ कार्यान्वित परियोजनाओं में आईआर को संबोधित करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों/आईए को प्रोत्साहित या अनिवार्य नहीं किया जाता है। आईएएस ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलए अधिनियम), 1894 का उपयोग करते हुए भूमि का अधिग्रहण करते हैं और भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण एलए अधिनियम और लागू राज्य नीतियों के आधार पर किया जाता है। एलए अधिनियम गैर-स्वामित्व धारकों को मान्यता नहीं देता है और उन्हें भूमि और संरचना के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है। नेशनल रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पालिसी (एनआरआरपी), 2007 भूमिहीन और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) गैर-स्वामित्व धारकों को मान्यता देती है, बशर्ते कि वे घोषणा की तारीख से कम से कम 5 वर्ष से लगातार निवास करते रहे हों। हालाँकि, एक नीति होने के कारण और अभी तक कोई नियम नहीं होने के कारण, इसे एनसीआर में राज्यों द्वारा नहीं अपनाया गया है। डोनर को सामाजिक प्रभावों और उन्हें कम करने के उपायों के उचित दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, प्रभावित लोगों को मुआवजे और अन्य सहायता का भुगतान करने के बाद ही सिविल कार्य शुरू किये जा सकते हैं।

3. ईएसएमएस की आवश्यकता

19. मौज़ूदा ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियाओं के आकलन से परियोजना की योजना, तैयारी, डिजाइन और कार्यान्वयन में पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को एकीकृत करने के लिए एक संरचित और व्यवस्थित तंत्र की आवश्यकता का पता चला। ईएसएमएस का उद्देश्य इस तरह की व्यवस्था करना है। ईएसएमएस के माध्यम से, एनसीआरपीबी के सुरक्षा प्रदर्शन को मजबूत किया जाएगा और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास के अनुरूप लाया जाएगा और डोनर आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करेगा।

4. ईएसएमएस के विकास की दिशा में दृष्टिकोण

20. ईएसएमएस के विकास के लिए दृष्टिकोण/पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मौजूदा परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों के लिए प्रासंगिक एनसीआरपीबी दस्तावेजों की समीक्षा, (ii) प्रासंगिक कानूनी आवश्यकताओं और अन्य समान प्रबंधन प्रणालियों/तैयार किए गए ढांचे का मिलान, (iii) एनसीआरपीबी और चयनित संभावित परियोजना प्रस्तावक/आईए के साथ चर्चा, (iv) ईएसएमएस के लिए एक मसौदा संरचना का विकास और चर्चा करना, (v) ईएसएमएस का मसौदा तैयार करना और (vi) ईएसएमएस के मसौदे पर चर्चा करना और विचार-विमर्श करना, और (vii) टिप्पणियों/चर्चाओं के अनुरूप ईएसएमएस के मसौदे को अंतिम रूप देना।

E. ईएसएमएस परिभाषित

21. यह ईएसएमएस एनसीआरपीबी द्वारा फाइनेंस किये गए परियोजनाओं के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों/जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों, प्रक्रियाओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है और अनिवार्य रूप से समग्र प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा है। एनसीआरपीबी वित्तीय मध्यस्थ (एफआई) परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कानूनों और डोनर (जैसे एडीबी) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी समग्र प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त ईएसएमएस स्थापित करेगा। ईएसएमएस में निम्नलिखित तत्व होंगे: (i) पर्यावरण और सामाजिक नीतियां, (ii) स्क्रीनिंग, वर्गीकरण और समीक्षा प्रक्रिया, (iii) पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों में कौशल और दक्षताओं सहित संगठनात्मक संरचना और स्टाफिंग; (iv) प्रशिक्षण आवश्यकताएं, और (v) निगरानी और रिपोर्टिंग।

F. ईएसएमएस का उद्देश्य

1. पर्यावरण

22. ईएसएमएस स्थापित करता है कि एनसीआरपीबी उन परियोजनाओं की तुलना में पर्यावरण सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के संबंध में क्या करेगा जो एनसीआरपीबी मदद करता है (अनुदान निधि का उपयोग करके) या आंशिक/पूर्ण वित्तपोषण (ऋण निधि का उपयोग करके) प्रदान करता है। ईएसएमएस विभिन्न प्रकार की परियोजना से संबंधित सुरक्षा मुद्दों को परिभाषित करता है, इन सुरक्षा मुद्दों से संबंधित विभिन्न लागू राष्ट्रीय कानूनी आवश्यकताओं की पहचान करता है, इन सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है, और परियोजना प्रस्तावक/आईए द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

23. यह ईएसएमएस बहुपक्षीय एजेंसियों (एडीबी, डब्ल्यूबी आदि) और द्विपक्षीय एजेंसियों (केएफडब्ल्यू, जेबीआईसी आदि) जैसे डोनर की पर्यावरणीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी काम करेगा। डोनर प्रक्रियाओं में सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनसीआरपीबी जैसे वित्तीय संस्थानों को प्रबंधन प्रणाली विकसित करने और संचालित करने की आवश्यकता होती है। यह ईएसएमएस उस आवश्यकता को पूरा करेगा।

2. सामाजिक

24. ईएसएमएस यह सुनिश्चित करता है कि एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित सभी परियोजनाएं आईआर और आईपी मुद्दों को ध्यान में रखती हैं, राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों के अनुरूप और डोनर की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसा लागू हो।

25. ईएसएमएस विभिन्न प्रकार की परियोजना के लिए सामाजिक सुरक्षा मुद्दों (आईआर और आईपी) को परिभाषित करता है, इन सुरक्षा मुद्दों से संबंधित विभिन्न लागू राष्ट्रीय कानूनी आवश्यकताओं की पहचान करता है, सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनाई जाने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है और परियोजना प्रस्तावक/आईए द्वारा क्या करने की आवश्यकता है, इस पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

G. ईएसएमएस की संरचना

26. ईएसएमएस में एक मेन वॉल्यूम और एक एनेक्स वॉल्यूम शामिल है। मेन वॉल्यूम में अलग-अलग खंड शामिल हैं जो निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

(i) एनसीआरपीबी और ईएसएमएस की पृष्ठभूमि (यह खंड),
(ii) लागू कानूनी आवश्यकताओं सहित सुरक्षा मुद्दों का विवरण,
(iii) पर्यावरण और सामाजिक नीतियां,
(iv) सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एनसीआरपीबी जिन परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा, उदाहरण के लिए स्क्रीनिंग और सुरक्षा उपायों का वर्गीकरण, परियोजना चक्र और सुरक्षा उपायों का प्रबंधन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, वार्षिक लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण और
(v) सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए संगठनात्मक व्यवस्था।.

27. मुख्य दस्तावेज़ प्रत्येक खंड और उप-खंड के भीतर पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को प्रासंगिक के रूप में एकीकृत करता है। अनुबंध में एक पर्यावरण अनुबंध और एक सामाजिक अनुबंध शामिल है। यह संदर्भ जानकारी प्रदान करता है जिसकी एनसीआरपीबी को (i) अपने स्वयं के संगठन के भीतर स्थापित ईएसएमएस को बनाए रखने और (ii) पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों पर परियोजना प्रस्तावक/आईए के प्रश्नों से निपटने में आवश्यकता होगी।

H. ईएसएमएस का रखरखाव

28. एनसीआरपीबी ने 1 अप्रैल, 2010 को ईएसएमएस की स्थापना की है और आगे ईएसएमएस का रखरखाव करेगा। यह ईएसएमएस पूरी तरह से संगठनात्मक प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकृत होगा। ईएसएमएस को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा, खासकर तब जब मौजूदा कानूनी आवश्यकताओं को संशोधित किया जाता है या नया कानून पेश किया जाता है। ईएसएमएस की व्यापक समीक्षा की जाएगी और हर तीसरे साल इसे संशोधित किया जाएगा। यह पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रकोष्ठ (ईएसएमसी) की जिम्मेदारी होगी।

II. सुरक्षा उपाय

A. अवलोकन

29. परियोजना संबंधी नकारात्मक प्रभाव हैं जिन्हें योजना, डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना है। इन प्रभावों में प्रमुख और मामूली और प्रतिवर्ती एवं अपरिवर्तनीय सामाजिक/सामुदायिक क्षति होने की संभावना है; साथ ही परियोजना में देरी, अधूरा कार्यान्वयन, परियोजना के विकास लक्ष्यों की आंशिक उपलब्धि और विभिन्न हितधारकों के लिए प्रतिष्ठा जोखिम इसके परिणाम हैं। इसलिए उचित सुरक्षा उपाय या सुरक्षा उपाय प्रबंधन परियोजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

1. पर्यावरण सुरक्षा

30. कई परियोजना संबंधी पर्यावरणीय प्रभाव हैं जिनके लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। इन प्रभावों में परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संचयी और प्रेरित प्रभाव शामिल हैं। प्रत्येक परियोजना को उसके प्रकार, स्थान, पैमाने और संवेदनशीलता और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भयावहता के अनुसार छानबीन करने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय प्रभावों में वे शामिल हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण (वायु, जल और भूमि); मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा और ट्रांस सीमा और वैश्विक पर्यावरणीय पहलू से संबंधित हैं।

31. पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय- नीतियां और आवश्यकताएं- प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से बचने, कम करने या न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं।

2. सामाजिक सुरक्षा

32. परियोजना से संबंधित सामाजिक प्रभावों में आईआर प्रभाव और आईपी पर प्रभाव शामिल हैं। मोटे तौर पर, भौतिक विस्थापन (स्थानांतरण, आवासीय भूमि का नुकसान या आश्रय का नुकसान) और आर्थिक विस्थापन (भूमि, संपत्ति, संपत्ति तक पहुंच, आय के स्रोत या आजीविका के साधन की हानि) आईआर प्रभाव हैं। अगर कोई परियोजना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आईपी की गरिमा, मानवाधिकारों, आजीविका प्रणालियों या संस्कृति को प्रभावित करती है या उन क्षेत्रों या प्राकृतिक या सांस्कृतिक संसाधनों को प्रभावित करती है जो आईपी के स्वामित्व, उपयोग, कब्जे या पैतृक डोमेन या संपत्ति के रूप में दावा करते हैं तो परियोजना से संबंधित आईपी प्रभाव शुरू होते हैं।

33. सामाजिक सुरक्षा उपाय- नीतियां और आवश्यकताएं- इन प्रतिकूल प्रभावों से बचने, कम करने या न्यूनतम करने का प्रयास करती हैं। आईआर से संबंधित, अगर इन प्रतिकूल प्रभावों से बचा नहीं जा सकता है, तो प्रभावित लोगों को सहायता/मुआवजा मिलनी चाहिए ताकि वे कम से कम उतने ही समृद्ध हों जितना कि वे परियोजना के पहले थे। आईपी से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय लोग शमन और प्रबंधन व्यवस्था के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी और मूल्यांकन में भाग लेते हैं।

B. कानूनी आवश्यकताएं

1. पर्यावरण

a. परिचय

34. एनसीआरपीबी की किसी भी भारतीय पर्यावरण कानून के तहत कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है - जो कि पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के ढांचे के तहत - अपने स्वयं के कामकाज की तुलना में है। लेकिन इसके परियोजना वित्तपोषण के संबंध में पर्यावरण कानून से संबंधित मुद्दे हैं जिनका परियोजना प्रस्तावक को पालन करने की आवश्यकता होगी। कानूनी जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की है। अपनी समग्र आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में, एनसीआरपीबी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये निवेश परियोजनाएँ अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं। ये काम एनसीआरपीबी अपनी मर्जी से कर रहा है। ये पहले से ही एनसीआरपीबी की मौजूदा प्रक्रियाओं में शामिल हैं।

b. संवैधानिक प्रावधान

35. संविधान का अनुच्छेद 48-A एक निर्देशक सिद्धांत प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। संविधान का अनुच्छेद 51-A भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित करता है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।

c. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006

36. भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 कवरेज का विस्तार करना चाहती है और राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति तथा पर्यावरण व विकास पर नीति वक्तव्य 1992 एवं प्रदूषण के उन्मूलन पर नीति वक्तव्य 1992 जैसी पिछली नीतियों पर अंतराल को भरना चाहती है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के उद्देश्य निम्न हैं:

- महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण
- इंट्रा-जेनरेशनल इक्विटी: गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा
- इंटर-जेनरेशनल इक्विटी
- आर्थिक और सामाजिक विकास में पर्यावरणीय चिंताओं का एकीकरण
- पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग में दक्षता

- पर्यावरण प्रशासन
- पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधनों में वृद्धि

d. पर्यावरण मूल्यांकन पर कानून

37. भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) 2006 की अधिसूचना भारत में पर्यावरण मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता निर्धारित करती है। इसमें कहा गया है कि निर्दिष्ट गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) आवश्यक है और इसे किसी भी निर्माण कार्य या भूमि की तैयारी (भूमि अधिग्रहण को छोड़कर) शुरू करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

e. अन्य प्रासंगिक पर्यावरण कानून

38. भारत में वर्तमान में लागू अधिनियम, नियम, नीतियां और विनियम निम्नलिखित हैं जो पर्यावरणीय मुद्दों से निपटते हैं जो बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर लागू होते हैं:

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, 1988 में संशोधन, और नियम
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 और नियम
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, 1987 में संशोधन, और नियम
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 1991 में संशोधित और निम्नलिखित नियम/अधिसूचना
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पर्यावरण मानक
- पर्यावरण (औद्योगिक परियोजनाओं के लिए साइटिंग) नियम, 1999
- पर्यावरण लेखापरीक्षा अधिसूचना, 1992
- खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989, 2000 में संशोधन
- खतरनाक सूक्ष्म जीवों और आनुवंशिक रूप से तैयार जीव या सेल नियम, 1989 का निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण
- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000
- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम, 1989, 2003 में संशोधन
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम, 1998, 2003 में संशोधन
- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000, 2002 में संशोधन
- रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996
- बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001
- पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्रों पर अधिसूचना: सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र और अरावली रेंज अधिसूचना, 1992
- सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
- वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 1993 में संशोधन और नियम
- वन अधिनियम, 1927
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, 1988 में संशोधन और निम्नलिखित नियम/दिशानिर्देश
- वन (संरक्षण) नियम, 1981 में 1992 और 2003 में संशोधन
- गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए दिशानिर्देश
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और नियम

39. भारत में पर्यावरण कानून का कार्यान्वयन राज्य का विषय है और अतः कार्यान्वयन प्रथाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं। इसलिए, एनसीआरपीबी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह प्रत्येक राज्य में कानून को लागू करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण की निगरानी करे की एनसीआरपीबी ने परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है या करेगा।

2. सामाजिक

a. परिचय

40. एनसीआरपीबी की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित किसी भी भारतीय कानून: राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारें और जनजातीय मामलों के मंत्रालय इन पर क्रमशः अमल कर रहे हैं। लेकिन परियोजना वित्तपोषण के संबंध में सामाजिक कानून से संबंधित मुद्दे भी हैं। अपनी समग्र आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में,एनसीआरपीबी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये निवेश परियोजनाएँ कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।

b. राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी)

41. एनआरआरपी 2007 में अस्तित्व में आया (और राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2007, भारतीय संसद में पेश किया गया है लेकिन अभी तक अपनाया नहीं गया है। यह समिति की मंजूरी के अधीन है और इसे आगामी संसद सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है)। एनआरआरपी व्यापक दिशानिर्देश और कार्यकारी निर्देश प्रदान करता है और यह सभी परियोजनाओं पर लागू होता है। एनआरआरपी के प्रावधान बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रदान किये जाते हैं और लोगों के अनैच्छिक विस्थापन के लिए अग्रणी सभी परियोजनाओं को व्यापक रूप से पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दों को संबोधित करते हैं।

c. भूमि अधिग्रहण (एलए) अधिनियम 1894

42. एलए अधिनियम आम तौर पर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को नियंत्रित करता है। अधिनियम, सार्वजनिक उद्देश्य या कंपनी के लिए आवश्यक भूमि को अधिसूचित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसमें जांच, आपत्तियों की सुनवाई और मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया भी शामिल है। अधिनियम घोषणा की तारीख से दो साल की समय सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर प्रक्रिया को पूरा करना होता है। एलए अधिनियम की समीक्षा की गई है और इसके प्रावधानों को एनआरआरपी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

d. अन्य प्रासंगिक सामाजिक कानून

43. निम्नलिखित अन्य प्रासंगिक सामाजिक कानून हैं:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 के प्रावधान
- संविधान (उनयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

3. डोनर की आवश्यकताएं

44. डोनर-बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियां जैसे एडीबी, डब्ल्यूबी, केएफडब्ल्यू, जेबीआईसी आदि- की सुरक्षा नीतियां हैं जो उनके उधारकर्ताओं के आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन सुरक्षा नीतियों के उद्देश्य हैं:

- जहां संभव हो, पर्यावरण और प्रभावित लोगों पर परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों से बचें;
- जब बचना संभव न हो तो पर्यावरण और प्रभावित लोगों पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, न्यूनतम करना और/या क्षतिपूर्ति करना; और
- उधारकर्ताओं/ग्राहकों को उनकी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों को प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करने में मदद करना।

45. डोनरों द्वारा सहयोग किये गए एफआई परियोजनाओं के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष आवश्यकताएं हैं क्योंकि इन एजेंसियों के पास एफआई द्वारा उधार दी जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में प्रत्यक्ष निरीक्षण या ज्यादा लाभ नहीं है। इसलिए, डोनर एफआई की व्यावसायिक प्रक्रियाओं और पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रबंधन के लिए उनकी क्षमता की समीक्षा करते हैं। सभी एफआई से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि उनके निवेश लागू राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं और वे वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए निषिद्ध निवेश गतिविधियों की सूची (जैसे दाता की निषिद्ध सूची) लागू करेंगे। जहां एफआई के निवेश में न्यूनतम या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम नहीं है, एफआई परियोजना को कोई नकारात्मक प्रभाव वाली परियोजना नहीं माना जाएगा और किसी अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी एफआई को एफआई की सम्पूर्ण प्रबंधन प्रणाली के एक हिस्से के रूप में बनाए रखने के लिए एफआई के संभावित पोर्टफोलियो की प्रकृति और जोखिमों के अनुरूप उचित ईएसएमएस स्थापित करने या जगह में होने की आवश्यकता होगी।

a. पर्यावरण सुरक्षा

46. पर्यावरण सुरक्षा नीतियों को आम तौर पर परिचालन नीतियों के रूप में समझा जाता है जो प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से बचने, कम करने या न्यूनतम करने की कोशिश करती हैं। इन नीतियों के लिए आवश्यक है कि प्रभावों की पहचान की जाए और परियोजना चक्र के शुरू में ही उनका मूल्यांकन किया जाए और संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचने, कम करने, न्यूनतम करने या क्षतिपूर्ति करने की योजनाओं को पूरे परियोजना चक्र में विकसित और कार्यान्वित किया जाए।

47. परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के महत्व को दर्शाने के लिए डोनर एक वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं। प्रत्येक परियोजना की जांच उसके प्रकार, स्थान, पैमाने और संवेदनशीलता और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की परिमाण के रूप में की जाती है। परियोजनाओं को निम्नलिखित चार श्रेणियों में से एक को सौंपा गया है:

श्रेणी	विवरण
A	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी A के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसके महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना है जो अपरिवर्तनीय, विविध या अभूतपूर्व हैं। तो ये प्रभाव भौतिक कार्यों के अधीन साइटों या सुविधाओं से बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।
B	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी B के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसके संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव श्रेणी A परियोजनाओं की तुलना में कम प्रतिकूल हैं। तो ये प्रभाव साइट-विशिष्ट हैं, कुछ यदि उनमें से कोई भी अपरिवर्तनीय है और ज्यादातर मामलों में न्यूनतम उपायों को श्रेणी A परियोजनाओं की तुलना में अधिक आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो एक प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा की आवश्यकता है
C	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी C के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसके न्यूनतम या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना नहीं है। तो किसी पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
FI	एक प्रस्तावित परियोजना को एफआई श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसमें किसी एफआई के लिए या उसके माध्यम से एडीबी निधियों का निवेश शामिल है।

स्रोतः एडीबी, सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट, जून 2009

48. पर्यावरण सुरक्षा उपायों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को नीचे दी गई तालिका में दिए गए तत्वों के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के उद्देश्य पर्यावरणीय सुदृढ़ता और परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करना और परियोजना निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरणीय विचारों के एकीकरण का सहयोग करना है।

इनमें प्रक्रिया आवश्यकताओं के साथ-साथ विषय-विशिष्ट आवश्यकताएं दोनों शामिल हैं। इन विषय-विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रयोज्यता प्रक्रिया की आवश्यकता, यानी पर्यावरण मूल्यांकन और अनुपालन के लिए स्थापित की गई है।

तालिका 2: पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकताएं

क्र.सं.	आवश्यकताएं
1	पर्यावरण मूल्यांकन
2	पर्यावरण योजना और प्रबंधन
3	सूचना प्रकटीकरण
4	परामर्श और भागीदारी
5	शिकायत निवारण तंत्र
6	निगरानी और रिपोर्टिंग
7	अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव
8	जैव विविधता संरक्षण और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (a) संशोधित आवास, (b) प्राकृतिक आवास, (c) महत्वपूर्ण आवास, (d) कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र, (e) आक्रामक अजनबी जातियां और (f) नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग
9	प्रदूषण की रोकथाम और कमी (a) प्रदूषण निवारण, संसाधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, (b) अपशिष्ट, (c) खतरनाक सामग्री, (d) कीटनाशक उपयोग और प्रबंधन, और (e) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
10.	स्वास्थ्य और सुरक्षा: (a) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, और (b) सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
11.	भौतिक सांस्कृतिक संसाधन

स्रोत: एडीबी सुरक्षा नीति विवरण, जून 2009 ये विश्व बैंक और केएफडब्ल्यू जैसे अन्य डोनरों के अनुरूप हैं।

49. **<u>भारत सरकार और डोनर सुरक्षा नीतियों के बीच तुलना</u>:** पर्यावरण सुरक्षा नीतियों से संबंधित भारत सरकार और डोनर की अधिकांश आवश्यकताएं समान हैं। सरकार और डोनर नीतियों के बीच एकमात्र अंतर श्रेणी B की आवश्यकताओं के संबंध में है। सरकार की नीति के अनुसार, कुछ सीमित पर्यावरणीय प्रभाव (श्रेणी B प्रकार) परियोजनाएं हैं जिनके लिए सीमित ईआईए या केवल एक प्रश्नावली प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए सरकारी नीति को हमेशा एक अलग ईआईए की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि दाता नीतियों के लिए एक सीमित पर्यावरणीय मूल्यांकन/प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) की आवश्यकता होती है।

b. सामाजिक सुरक्षा

50. सामाजिक सुरक्षा नीतियों को आम तौर पर परिचालन नीतियों के रूप में समझा जाता है जो आईपी पर प्रतिकूल आईआर और/या प्रभावों से बचने, कम करने या न्यूनतम करने की कोशिश करती हैं। इन नीतियों के लिए आवश्यक है कि प्रभावों की पहचान की जाए और परियोजना चक्र के शुरू में ही उनका मूल्यांकन किया जाए और संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचने, कम करने, न्यूनतम करने या क्षतिपूर्ति करने की योजनाओं को पूरे परियोजना चक्र में विकसित और कार्यान्वित किया जाए।

51. परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभावों के महत्व को दर्शाने के लिए डोनर एक वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं। प्रत्येक परियोजना की जांच उसके प्रकार, स्थान, पैमाने, संवेदनशीलता और उसके संभावित सामाजिक प्रभावों के परिमाण के रूप में की जाती है। परियोजनाओं को आईआर और आईपी के आधार पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में से एक को सौंपा गया है:

तालिका 3: सामाजिक सुरक्षा वर्गीकरण

श्रेणी	विवरण - आईआर	विवरण - आईपी
A	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी A के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि 200 या अधिक लोग प्रमुख प्रभावों का अनुभव करेंगे, जिन्हें (i) आवास से भौतिक रूप से विस्थापित होने या (ii) उनकी उत्पादक संपत्तियों (आय सृजन) का 10% या उससे अधिक हानि होने के रूप में परिभाषित किया गया है।	परियोजनाओं से स्थानीय लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण प्रभाव वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों की गरिमा, मानवाधिकारों, आजीविका प्रणालियों या संस्कृति को प्रभावित करते हैं या उन क्षेत्रों या प्राकृतिक या सांस्कृतिक संसाधनों को प्रभावित करते हैं जो स्थानीय लोग अपने पैतृक डोमेन के रूप में उपयोग, अधिकार या दावा करते हैं।
B	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी B के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि संभावित प्रतिकूल प्रमुख (जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है) प्रभाव हैं जो 200 से कम लोगों का अनुभव करेंगे या कोई मामूली प्रभाव होंगे।	ऐसी परियोजनाएँ जिनमें स्थानीय लोग एकमात्र या परियोजना के लाभार्थियों की भारी संख्या और जब केवल सकारात्मक प्रभावों की पहचान की जाती है।
C	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी C के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है।	स्थानीय लोगों पर कोई प्रभाव परिकल्पित नहीं है।
FI	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी एफआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसमें किसी वित्तीय मध्यस्थ के लिए या उसके माध्यम से एडीबी निधियों का निवेश शामिल है।	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी एफआई रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसमें किसी वित्तीय मध्यस्थ के लिए या उसके माध्यम से एडीबी निधियों का निवेश शामिल है।

52. सामाजिक सुरक्षा और उसके तत्वों की विशिष्ट आवश्यकताओं को निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है। ये डोनरों की आवश्यकताएं हैं और इसमें प्रक्रिया आवश्यकताओं के साथ-साथ विषय-विशिष्ट आवश्यकताएं दोनों शामिल हैं। इन विषय-विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रयोज्यता प्रक्रिया की आवश्यकता यानी सामाजिक मूल्यांकन और अनुपालन के लिए स्थापित है।

तालिका 4: सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएं - आईआर

क्र.सं.	आवश्यकताएं
1	सामाजिक प्रभाव आकलन
2	पुनर्वास योजना
3	सूचना प्रकटीकरण
4	परामर्श और भागीदारी
5	शिकायत निवारण तंत्र
6	निगरानी और रिपोर्टिंग
7	अप्रत्याशित अनैच्छिक पुनर्वास प्रभाव
8	स्थानीय लोगों के लिए 8 विशेष विचार

तालिका 5: सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएँ - आई.पी

क्र.सं.	आवश्यकताएं
1	परामर्श और भागीदारी
2	सामाजिक प्रभाव आकलन
3	स्थानीय लोग योजना
4	जानकारी प्रकटीकरण
5	शिकायत निवारण तंत्र

[2] एडीबी की सुरक्षा नीति विवरण का अनुपालन, 2009

क्र.सं.	आवश्यकताएं
6	निगरानी और रिपोर्टिंग
7	स्थानीय लोगों पर अप्रत्याशित प्रभाव को संबोधित करना
8	पैतृक डोमेन और भूमि और संबंधित प्राकृतिक संसाधन a. स्थानीय लोगों के प्रथागत अधिकारों का संरक्षण b. पैतृक डोमेन के लिए सुरक्षा c. पैतृक भूमि और संसाधनों के लिए जिम्मेदार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण d. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रथाओं का संरक्षण e. आजीविका प्रणालियों का पुनर्वास
9	प्रभावित स्थानीय लोगों के समुदायों की सहमति
10	सांस्कृतिक संसाधनों के व्यावसायिक विकास में समान हिस्सेदारी प्राप्त करना
11	प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक विकास में समान हिस्सेदारी प्राप्त करना

53. <u>सरकार और डोनर सुरक्षा नीति के बीच तुलना</u>: निम्न तालिका सरकारी नीति और डोनर नीति/प्रक्रियाओं के बीच प्रमुख सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं की तुलना करती है।.

54. एनसीआरपीबी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण और भूमि और संपत्ति के मुआवजे को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय और राज्य कानूनों के अनुपालन में हैं। हालांकि, राष्ट्रीय कानून दाता सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ भिन्न हैं। परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए कि एनसीआरपीबी फंड राष्ट्रीय कानूनों और दाता सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, एनसीआरपीबी ने यह ईएसएमएस तैयार किया है। प्रमुख क्षेत्र जहां राष्ट्रीय कानून डोनर सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ भिन्न हैं, निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है कि कैसे एनसीआरपीबी अपने ईएसएमएस के माध्यम से अंतर को दूर करता है।

तालिका 6: राष्ट्रीय/राज्य कानूनों और डोनर सुरक्षा आवश्यकता के बीच मौलिक अंतर

क्र.सं	राष्ट्रीय / राज्य कानून	डोनर सुरक्षा आवश्यकताएं	एनसीआरपीबी एसएमएस जो गैप को दूर करता है	टिप्पणियां
1	एलए अधिनियम के अनुसार भूमि के लिए मुआवजा (दिशानिर्देश मूल्य/पिछले बिक्री आंकड़ों के आधार पर)	प्रतिस्थापन मूल्य पर भूमि का मुआवजा[3]	एलए अधिनियम के अनुसार भूमि के लिए मुआवजा।	मुआवजा पिछले बिक्री आंकड़ों (सर्किल दरों / दिशानिर्देश मूल्य) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हालांकि, अगर ईएसएमसी को पता चलता है कि इस तरह निर्धारित मुआवजा भूमि के प्रतिस्थापन मूल्य से कम है, तो परियोजना प्रस्तावक/आईए अंतर को सहायता के रूप में प्रदान करेगा।
2	संरचना मूल्यह्रास के साथ मुआवजा दिया	मूल्यह्रास के बिना प्रतिस्थापन लागत पर संरचना की भरपाई की जाएगी	मूल्यह्रास के बिना प्रतिस्थापन लागत पर संरचना की भरपाई की जाएगी	-
3	संपत्ति के नुकसान के लिए गैर-स्वामित्व धारक मुआवजे के लिए पात्र नहीं हैं	संपत्ति के नुकसान के लिए गैर-स्वामित्व धारक मुआवजे के हकदार हैं (भूमि के लिए नहीं)	संपत्ति के नुकसान के लिए गैर-स्वामित्व धारकों ने मुआवजा दिया (भूमि के लिए नहीं)	एनआरआरपी गैर-स्वामित्वधारकों को मान्यता देता है जो भूमिहीन और बीपीएल हैं, यदि वे घोषणा की तारीख से पहले कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए लगातार निवास करते हैं

[3] प्रतिस्थापन मूल्य/लागत एक प्रभावित व्यक्ति के लिए खुले बाजार में खरीद के माध्यम से नुकसान हुई भूमि/परिसंपत्ति को बदलने के लिए आवश्यक राशि है।

क्र.सं	राष्ट्रीय / राज्य कानून	डोनर सुरक्षा आवश्यकताएं	एनसीआरपीबी एसएमएस जो गैप को दूर करता है	टिप्पणियां
4	आजीविका के नुकसान के लिए कोई सहायता नहीं	आजीविका (भूमि/वाणिज्यिक) के नुकसान के लिए आजीविका सहायता	आजीविका (भूमि/वाणिज्यिक) के नुकसान के लिए प्रदान की गई आजीविका सहायता	हरियाणा में, भूस्वामियों के लिए आजीविका के नुकसान को वार्षिकी के रूप में प्रदान किया जाता है (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि के साथ 33 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रति एकड़) एनआरआरपी छोटे व्यापारियों को पुनर्वास अनुदान, निर्वाह भत्ता और आय की हानि के लिए सहायता प्रदान करता है
5	कमजोरों के लिए कोई सहायता नहीं	कमजोर लोगों के लिए अतिरिक्त सहायता	कमजोर लोगों के लिए अतिरिक्त सहायता	कमजोर व्यक्ति जैसे विकलांग, निराश्रित, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियां, परित्यक्त महिलाएं, या पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान नहीं की जाती है या तुरंत प्रदान नहीं की जा सकती है और जो अन्यथा परिवार (एनआरआरपी 2007) के एक हिस्से के रूप में शामिल नहीं हैं एनआरआरपी कमजोर लोगों को जीवन के लिए पेंशन प्रदान करता है
6	आईपी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं	सकारात्मक और/या नकारात्मक प्रभाव के लिए एक आईपीपी की आवश्यकता होगी	यदि परियोजना में आईपी पर प्रभाव शामिल है तो आईपीपी तैयार किया जाएगा	यदि परियोजना में 200 या अधिक जनजातीय परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, तो एनआरआरपी को जनजातीय विकास योजना की आवश्यकता है।
7	बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं	समझौता बातचीत के माध्यम से भूमि और अन्य संपत्तियों का अधिग्रहण अस्वैच्छिक पुनर्वास पर सुरक्षा आवश्यकताओं को आकर्षित नहीं करता है	आइए को समझौता वार्ता के माध्यम से भूमि और अन्य संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है - अनैच्छिक पुनर्वास पर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं बातचीत के जरिए हुए भूमि अधिग्रहण पर लागू नहीं होती हैं	यूआईटी-अलवर और एसएडीए-ग्वालियर में बातचीत के जरिए भूमि अधिग्रहण के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं

C. क्षेत्रीय योजना

55. सभी परियोजना-वित्तपोषण गतिविधियों को क्षेत्रीय योजना के अनुकूल होना चाहिए। एनसीआरपीबी इस अनुकूलता को सुनिश्चित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इस योजना में पर्यावरण और सामाजिक सरोकार शामिल हैं और प्रतिबिंबित होते हैं। योजना के साथ संगतता सुनिश्चित करने के माध्यम से, एनसीआरपीबी उन परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन और रखरखाव में सुरक्षा उपायों को भी शामिल करेगा,

जिनको वह फाइनेंस करता है। उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय योजना में पर्यावरणीय मुद्दों पर एक अलग अध्याय शामिल है। इस अध्याय में, एक प्रतिबद्धता है कि सभी एनसीआरपीबी को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय पर्यावरण कानूनों का पालन करना चाहिए। इस प्रतिबद्धता को लागू करके, एनसीआरपीबी पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित कर रहा है।

III. एनसीआरपीबी की पर्यावरण और सामाजिक नीतियां

A. पर्यावरण नीति

56. एनसीआरपीबी अपने सभी कार्यों (स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, अप्रेजल और निगरानी) में प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन कार्यों को सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करेगा।

- इसके संचालन में नकारात्मक पर्यावरणीय (स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित) प्रभावों को कम करना और पर्यावरण (विशेष रूप से पारिस्थितिक क्षेत्रों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों) और उन लोगों के जोखिमों को कम करना जो अनुरूप योजनाओं को तैयार करने और लागू करने से प्रभावित हो सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय - लागू भारतीय पर्यावरण कानून और डोनरों की आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित - परियोजना प्रस्तावक / आईए द्वारा इसके वित्तपोषण से पहले और परिचालन चरण के दौरान इसके कार्यान्वयन में योजना, डिजाइन, निर्माण में पर्याप्त रूप से एकीकृत किए जा रहे हैं।
- सभी लागू राष्ट्रीय और स्थानीय पर्यावरण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- प्रोत्साहित करना कि परियोजना प्रस्तावक/आईए द्वारा सार्वजनिक और हितधारक परामर्श किया जाए और परियोजना चक्र के सभी चरणों में आवश्यक जानकारी का खुलासा करना।
- इसके समग्र आंतरिक जोखिम प्रबंधन विश्लेषण में पर्यावरणीय जोखिम को एकीकृत करना।
- परियोजना चक्र के सभी चरणों में परियोजना प्रस्तावक/आईए के साथ संचालन और बातचीत के सभी पहलुओं में पर्यावरण प्रबंधन के विचारों को शामिल करना।

यह नीति विवरण एनसीआरपीबी की पर्यावरण सुरक्षा उपायों के प्रति संवेदनशीलता, चिंता और प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

B. सामाजिक नीति

57. एनसीआरपीबी लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सामाजिक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए। एनसीआरपीबी इस दिशा में काम करेगा:

- परियोजना और डिजाइन विकल्पों की खोज करके अनैच्छिक पुनर्वास और स्थानीय लोगों के प्रभावों को टालना या कम करना।
- ऐसे मामलों में, जहां आईआर और आईपी पर प्रभाव अपरिहार्य हैं, पूर्व-परियोजना स्तरों के सापेक्ष वास्तविक रूप से सभी प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका को बढ़ाना या कम से कम बहाल करना।
- विस्थापित गरीबों और अन्य कमजोर समूहों के जीवन स्तर में सुधार करना।
- स्थानीय लोगों पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से संबोधित करना; यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि वे सांस्कृतिक रूप से उचित सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करें और उन्हें प्रभावित करने वाली परियोजनाओं में परामर्श और सक्रिय भागीदारी सहित पारदर्शी तंत्र भी सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित व्यक्ति यथासंभव वित्तपोषित परियोजनाओं से लाभान्वित हों और परियोजना की योजना से कार्यान्वयन तक परियोजना के विभिन्न चरणों में उनसे परामर्श करना।

- परियोजना की समग्र तैयारी और कार्यान्वयन के साथ आरपी और आईपीपी को एकीकृत करना और सिविल कार्य सौंपने से पहले मुआवजे और अन्य सहायता का भुगतान करना।

यह नीति विवरण एनसीआरपीबी की संवेदनशीलता, चिंता और सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

58. ये दोनों नीतियां प्रतिबद्ध हैं कि एनसीआरपीबी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जिन परियोजनाओं का वह मदद करता है वे सरकार की नीतियों के साथ-साथ डोनर नीतियों को पूरा करती हैं।

IV. संचालन संबंधी प्रक्रियाएं

A. स्क्रीनिंग और वर्गीकरण

59. यह एनसीआरपीबी के लिए परियोजनाओं को उनके पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है।

1. पर्यावरण

60. प्रारंभिक परियोजना चरण के एक भाग के रूप में, परियोजना प्रस्तावक/आईए को एक चेकलिस्ट को पूरा करके बुनियादी पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करनी होती है। चेकलिस्ट से महत्वपूर्ण जानकारी दो तरह की होगी: (i) क्या परियोजना के महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे, सीमित प्रभाव होंगे या कोई प्रभाव नहीं होंगे; और (ii) क्या परियोजना पारिस्थितिक क्षेत्र में है या नहीं। इसके अलावा, परियोजना-विशिष्ट पर्यावरण चेकलिस्ट को भी पूरा किया जाएगा।

61. इस चेकलिस्ट में दी गई जानकारी के आधार पर, एनसीआरपीबी निम्नलिखित तालिका का उपयोग करके परियोजना को पर्यावरणीय श्रेणियों-E1, E2 और E3 में वर्गीकृत करेगा।

तालिका 7: पर्यावरण वर्गीकरण

पर्यावरण परिदृश्य	एनसीआरपीबी का वर्गीकरण	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का वर्गीकरण	एडीबी वर्गीकरण
महत्वपूर्ण प्रभाव या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में	E1	A	A
सीमित प्रभाव	E2	B1 या B2 या कोई श्रेणी नहीं	B
कोई प्रभाव नहीं	E3	कोई श्रेणी नहीं	C

62. विभिन्न परिदृश्यों की परिभाषा निम्नानुसार है:

- महत्वपूर्ण प्रभाव या पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में: यदि परियोजना के महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हैं जो अपरिवर्तनीय, विविध या अभूतपूर्व हैं, तो इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रभाव भौतिक कार्यों के अधीन साइटों या सुविधाओं से बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जाएगा। एनसीआर क्षेत्रीय योजना में, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में आरक्षित/संरक्षित वन, आरक्षित और संरक्षित वनों के अलावा अन्य वन, स्मारक (राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय), विरासत/सांस्कृतिक स्थल, दर्शनीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, लुप्तप्राय प्रजातियों वाले क्षेत्र - वनस्पति और जीव, जीवमंडल भंडार, आर्द्रभूमि, रिसॉर्ट्स/पर्यटक रुचि के क्षेत्र, जल निकाय, झरने/जल पुनर्भरण क्षेत्र, और अन्य पर्यावरणीय संसाधन क्षेत्र शामिल हैं। एनसीआर में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के उदाहरण सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और अरावली रेंज हैं।

- सीमित पर्यावरणीय प्रभाव: अगर परियोजना के ऐसे प्रभाव हैं जो साइट-विशिष्ट हैं, यदि उनमें से कुछ अपरिवर्तनीय हैं तो ज्यादातर मामलों में न्यूनतम उपाय तैयार किए जा सकते हैं।
- कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं: यदि परियोजना के न्यूनतम या कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना नहीं है, तो इसे इस पर्यावरणीय परिदृश्य के रूप में माना जाता है।

63. तालिका परियोजना के संभावित एमओईएफ वर्गीकरण के साथ-साथ एडीबी वर्गीकरण भी प्रदान करती है। एमओईएफ के लिए, एक परियोजना को A, B1 या B2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण परियोजना के प्रकार, आकार और स्थान की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। E2 परियोजनाओं के लिए, एनसीआरपीबी ईआईए अधिसूचना 2006 का उपयोग करके एमओईएफ श्रेणी का निर्धारण करेगा।

64. एक बार एमओईएफ श्रेणी निर्धारित हो जाने के बाद, एनसीआरपीबी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना प्रस्तावक/आईए उनकी एमओईएफ प्रक्रिया और निम्नलिखित प्रवाह चार्ट में दिए गए आवश्यकताओं का पालन करता है।

एमओईएफ पर्यावरण वर्गीकरण

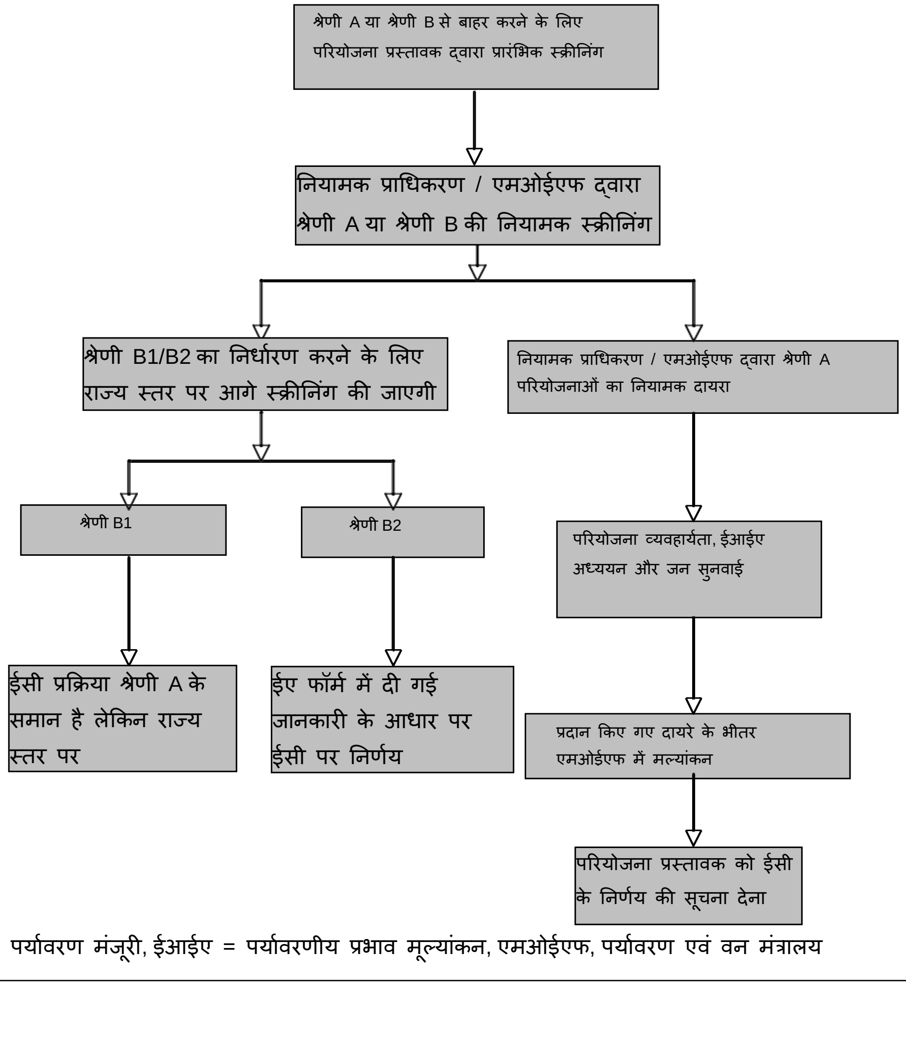

कैट = श्रेणी, ईसी = पर्यावरण मंजूरी, ईआईए = पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, एमओईएफ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

65. एमओईएफ के लिए, श्रेणी A और B1 के तहत परियोजनाओं को एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की आवश्यकता होती है और क्रमशः एमओईएफ और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी के लिए संसाधित किया जाता है। श्रेणी B 2 को ईआईए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समीक्षा के लिए राज्य के पर्यावरण विभाग को निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। एमओईएफ के लिए, श्रेणी B1 के तहत परियोजनाओं को A के रूप में फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है अगर साइट संवेदनशीलता पर विचार करने वाली सामान्य शर्तों (जीसी) का उल्लंघन किया जाता है। एनसीआरपीबी और एमओईएफ की ईआईए आवश्यकताओं के बीच समानता निम्नलिखित तालिका में दी गयी है।

तालिका 8: वर्गीकरण और आवश्यकताएँ

एनसीआरपीबी का वर्गीकरण	एमओईएफ का वर्गीकरण	एनसीआरपीबी की ईआईए आवश्यकताएँ	एमओईएफ की ईआईए आवश्यकताएँ
E1	A	पूर्ण ईआईए	पूर्ण ईआईए (एमओईएफ स्तर)
E2	B1	सीमित ईआईए/आईईई	सीमित ईआईए (राज्य स्तर) विस्तृत
	B2	सीमित ईआईए/आईईई	प्रश्नावली (राज्य स्तर)
E3	कोई श्रेणी नहीं	सीमित ईआईए/आईईई	कोई ईआईए की आवश्यकता नहीं
	कोई श्रेणी नहीं	कोई ईआईए की आवश्यकता नहीं	कोई ईआईए की आवश्यकता नहीं

66. उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि एनसीआरपीबी और एमओईएफ वर्गीकरण के आधार पर ईआईए आवश्यकताओं के बीच काफी समानता है। अंतर यह है कि एनसीआरपीबी को E2 परियोजनाओं के लिए एक सीमित ईआईए/आईईई की आवश्यकता होती है, जबकि एमओईएफ को या तो (i) B2 एमओईएफ श्रेणी के लिए राज्य-स्तरीय समाशोधन निकाय से ईसी प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली के रूप में समान जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है या (ii) कोई ईआईए नहीं यदि यह B2 एमओईएफ श्रेणी के रूप में नहीं आता है।

67. एक बार एनसीआरपीबी का पर्यावरण वर्गीकरण हो जाने के बाद, उपयुक्त ईआईए आवश्यकता को परियोजना प्रस्तावक/आईए को निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अलावा, एनसीआरपीबी एमओईएफ वर्गीकरण के परियोजना प्रस्तावक/आईए को भी सलाह देगा और परियोजना प्रस्तावक/आईए द्वारा क्या किया जाना चाहिए।

2. सामाजिक

68. प्रारंभिक परियोजना चरण के एक भाग के रूप में, परियोजना प्रस्तावक/आईए को एक आईआर और आईपी चेकलिस्ट को पूरा करके बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होती है। सामाजिक सुरक्षा उपायों पर, निम्नलिखित तीन-स्तरीय वर्गीकरण का पालन किया जाएगा। यह डोनर आवश्यकताओं पर आधारित है।

तालिका 9: सामाजिक वर्गीकरण

आईआर और आईपी परिदृश्य	एनसीआरपीबी का वर्गीकरण	एनसीआरपीबी का वर्गीकरण	डोनर[a] वर्गीकरण
महत्वपूर्ण प्रभाव	S1	मैदानी इलाकों में ≥400 एपी आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में ≥200 एपी	A
	S1	मैदानी इलाकों में >200 और <400 एपी > 100 और <200 एपी में आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्र	A
सीमित प्रभाव	S2	मैदानी क्षेत्रों में ≤200 एपी आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में ≤100 एपी	B
कोई प्रभाव नहीं	S3	कोई प्रभाव नहीं	C

[a] एडीबी। 2009. सुरक्षा नीति विवरण। मनीला।

69. एनसीआरपीबी के सामाजिक वर्गीकरण के आधार का वर्णन निम्न तालिका में किया गया है।

श्रेणी	विवरण - आईआर	विवरण - आईपी
S1	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी A के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि 200 या अधिक लोग प्रमुख प्रभावों का अनुभव करेंगे, जिन्हें (i) आवास से भौतिक रूप से विस्थापित होने या (ii) उनकी उत्पादक संपत्तियों (आय सृजन) का 10% या उससे अधिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है।	परियोजनाओं से स्थानीय लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण प्रभाव वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों की गरिमा, मानवाधिकारों, आजीविका प्रणालियों, या संस्कृति को प्रभावित करते हैं या उन क्षेत्रों या प्राकृतिक या सांस्कृतिक संसाधनों को प्रभावित करते हैं जो स्थानीय लोग अपने पैतृक डोमेन के रूप में उपयोग, अधिकार या दावा करते हैं।
S2	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी B के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि संभावित प्रतिकूल प्रमुख (जैसा कि पहले परिभाषित किया गया है) प्रभाव हैं जो 200 से कम लोगों का अनुभव करेंगे या कोई मामूली प्रभाव होंगे।	ऐसी परियोजनाएँ जिनमें स्थानीय लोग एकमात्र या परियोजना के लाभार्थियों की ज्यादा संख्या है और जब केवल सकारात्मक प्रभावों की पहचान की जाती है।
S3	एक प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी C के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अगर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है।	स्थानीय लोगों पर किसी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है।

70. विभिन्न श्रेणियों के लिए, एनसीआरपीबी के दस्तावेजों की आवश्यकता निम्नलिखित तालिका में शामिल है:

तालिका 10: वर्गीकरण और आवश्यकताएँ

एनसीआरपीबी का वर्गीकरण	एनसीआरपीबी की आईआर आवश्यकताएँ	एनसीआरपीबी की आईपी आवश्यकताएँ
S1	आरपी	आईपीपी
S2	एसआरपी	परियोजना दस्तावेज में आईपी पर संक्षिप्त टिप्पणी
S3	कोई आरपी या एसआरपी की आवश्यकता नहीं है	कोई आईपीपी या संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक नहीं है

71. एनआरआरपी 2007 के तहत एनसीआरपीबी और भारत सरकार की आवश्यकताओं की तुलना निम्नलिखित तालिका में शामिल है।

तालिका 11: वर्गीकरण और आवश्यकताओं की तुलना

एनसीआरपीबी का वर्गीकरण	एनआरआरपी का वर्गीकरण	एनसीआरपीबी का वर्गीकरण		एनआरआरपी का वर्गीकरण	
		आईआर	आईपी	आईआर	आईपी
S1	मैदानी इलाकों में ≥400 एपी आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में ≥200 एपी	RP	आईपीपी	पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना (आरआरपी)	जनजातीय विकास योजना (टीडीपी)
S1	मैदानी इलाकों में >200 और <400 एपी आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में >100 और <200 एपी	RP	आईपीपी	पर्याप्त व्यवस्था	पर्याप्त व्यवस्था
S2	मैदानी इलाकों में ≤200 एपी आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में ≤100 एपी	SRP	परियोजना दस्तावेज में आईपी पर संक्षिप्त टिप्पणी	पर्याप्त व्यवस्था	पर्याप्त व्यवस्था

एनसीआरपीबी का वर्गीकरण	एनआरआरपी का वर्गीकरण	एनसीआरपीबी का वर्गीकरण		एनआरआरपी का वर्गीकरण	
		आईआर	आईपी	आईआर	आईपी
S3	कोई नहीं	कोई आरपी या एसआरपी आवश्यक नहीं है	कोई आईपीपी या संक्षिप्त नोट की आवश्यकता नहीं है	कोई नहीं	कोई नहीं

72. उपरोक्त सभी से, यह स्पष्ट है कि एनसीआरपीबी और डोनरों के आधार पर आवश्यकताओं के बीच पूर्ण समानता है। भारत सरकार की आवश्यकताओं, यानी एनआरआरपी 2007 के संदर्भ में, ऐसी परियोजनाएँ जहाँ मैदानी क्षेत्रों में 400 या अधिक लोग प्रभावित हैं और 200 या अधिक लोग आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावित हैं, जिनका सामाजिक प्रभाव का आकलन करना तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपाय / योजना (आरआरपी) तैयार करना अनिवार्य है। इसके अलावा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक प्रशासक और आयुक्त (जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं) नियुक्त करने की आवश्यकता है। उन परियोजनाओं के लिए जहां मैदानी क्षेत्रों में 400 से कम और आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों में 200 से कम प्रभावित व्यक्ति हैं, संबंधित राज्य सरकार/एजेंसी को एक प्रशासक नियुक्त करना चाहिए और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। यदि परियोजना में 200 या अधिक आदिवासी परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, तो एनआरआरपी को एक जनजातीय विकास योजना की आवश्यकता है।

B. सुरक्षा मार्गदर्शन - परियोजना प्रस्तावक / आईए के साथ साझा करना

73. यह प्रक्रिया सुरक्षा आवश्यकताओं पर परियोजना प्रस्तावक/आईए को मार्गदर्शन जानकारी साझा करने के लिए है।

74. जब परियोजना प्रस्तावक/आईए प्रारंभिक परियोजना अवधारणा के साथ एनसीआरपीबी से संपर्क करता है, तो एनसीआरपीबी स्क्रीनिंग और वर्गीकरण प्रक्रिया के आधार पर एनसीआरपीबी पर्यावरण और सामाजिक श्रेणी का निर्धारण करेगा।

75. र्गीकरण के आधार पर, एनसीआरपीबी सलाह देगा कि परियोजना प्रस्तावक/आईए को अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए।

76. श्रेणी E1 और S1 परियोजनाओं के लिए, एनसीआरपीबी परियोजना प्रस्तावक/आईए को सलाह देगा कि डोनर प्रारंभिक चरणों से मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होगा और यह डोनर वर्गीकरण के आधार पर श्रेणी A परियोजना के बराबर है। इसके ड्यू -डिलिजेंस के भाग के रूप में, डोनर (i) वित्तीय मध्यस्थ द्वारा एकत्रित पर्यावरण और सामाजिक जानकारी की समीक्षा करेगा, (ii) आवश्यक अतिरिक्त जानकारी निर्धारित करेगा, (iii) उचित शमन उपायों को निर्धारित करने में सहायता करेगा, और (iv) शर्तों को निर्दिष्ट करेगा जिसके तहत परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए, डोनर परियोजना अनुमोदन से पहले ईआईए, आरपी, और/या आईपीपी, यदि लागू हो, को मंजूरी देगा और परियोजना टीम यह सुनिश्चित करेगी कि निम्नलिखित दस्तावेजों : (i) ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट कम से कम 120 दिन परियोजना के अनुमोदन से पहले, और (ii) परियोजना के अनुमोदन से पहले मसौदा आरपी और मसौदा आईपीपी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं।

77. श्रेणी E2 और S2 परियोजनाओं के लिए, एनसीआरपीबी डोनर की सहमति प्राप्त करने के बाद ही ईएसएमएस प्रक्रियाओं का पालन करेगा कि एनसीआरपीबी ने मूल्यांकन/ड्यू -डिलिजेंस प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त इन-हाउस क्षमता का निर्माण किया है। उस चरण तक, एनसीआरपीबी मूल्यांकन/उचित परिश्रम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में डोनर को शामिल करेगा।

78. पर्यावरणीय पहलुओं पर, एनसीआरपीबी परियोजना के प्रकार के आधार पर परियोजना प्रस्तावक / आईए के साथ संबंधित अनुबंधों को साझा करेगा और इंगित करेगा कि आवश्यकताएं कमोबेश उसी के अनुरूप हैं जो परियोजना प्रस्तावक / आईए को एमओईएफ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना होगा।

79. सामाजिक पहलुओं पर, एनसीआरपीबी परियोजना प्रस्तावक/आईए के साथ सामाजिक सुरक्षा ढांचे को साझा करेगा। एनसीआरपीबी से सहायता प्राप्त करते समय परियोजना प्रस्तावकों/आईए को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

- आईआर और आईपी प्रभावों के लिए स्क्रीन परियोजना प्रस्ताव और अस्वैच्छिक पुनर्वास स्क्रीनिंग चेकलिस्ट और स्थानीय लोगों की स्क्रीनिंग चेकलिस्ट जमा करना;
- अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों के महत्व के अनुरूप पुनर्स्थापन योजना (आरपी) तैयार करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के हिस्से के रूप में इसे प्रस्तुत करना ;
- स्थानीय लोगों पर संभावित प्रभाव के महत्व के अनुरूप स्थानीय लोग योजना (आईपीपी) तैयार करना और डीपीआर के हिस्से के रूप में इसे प्रस्तुत करना;
- विस्तृत डिजाइन के पूरा होने पर या परियोजना डिजाइन में बदलाव के मामले में अपडेट किया हुआ आरपी और/या आईपीपी जमा करना;
- आरपी और/या आईपीपी को लागू करना और एनसीआरपीबी के ईएसएमसी को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- समय-समय पर आरपी और/या आईपीपी की निगरानी करना और ईएसएमसी को रिपोर्ट देना। एस-1 परियोजनाओं के लिए निगरानी और मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाएगा; और
- ऋण समापन को आरपी और/या आईपीपी के लिए की गई गतिविधियों के संतोषजनक समापन से जोड़ा जाएगा।

80. ईएसएमएस को एनसीआरपीबी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रिंट प्रतियां अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

81. सुविधाओं और/या व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जो पहले से मौजूद हैं या निर्माणाधीन हैं, एनसीआरपीबी परियोजना प्रस्तावक/आईए को सलाह देगा कि वे अतीत या वर्तमान से संबंधित चिंताओं की पहचान करने के लिए ऑन-साइट मूल्यांकन सहित प्रभावों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा अनुपालन ऑडिट करेंगे।

82. जहां कहीं भी एनसीआरपीबी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने जैसी परियोजना तैयार करने में सहायता कर रहा है, एनसीआरपीबी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसकी अनुदान निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता सुरक्षा मूल्यांकन के लिए भी प्रदान की जाती है या तो विस्तृत या सीमित, जैसा भी मामला हो।

83. एक बार जब परियोजना स्वीकृत हो जाती है और कार्यान्वयन शुरू हो जाता है, तो एनसीआरपीबी अपने प्रबंधन क्षमता निर्माण सलाहकारों के माध्यम से सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण, कार्यान्वयन सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

C. परियोजना चक्र और सुरक्षा हस्तक्षेप/सत्यापन

84. यह प्रक्रिया परियोजना चक्र के दौरान सुरक्षा आवश्यकताओं के पालन को सत्यापित करने के लिए है।

1. पर्यावरण

85. ओवरले के रूप में पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ एनसीआरपीबी का परियोजना चक्र नीचे फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है।

फ्लो चार्ट: परियोजना चक्र और पर्यावरण सुरक्षा

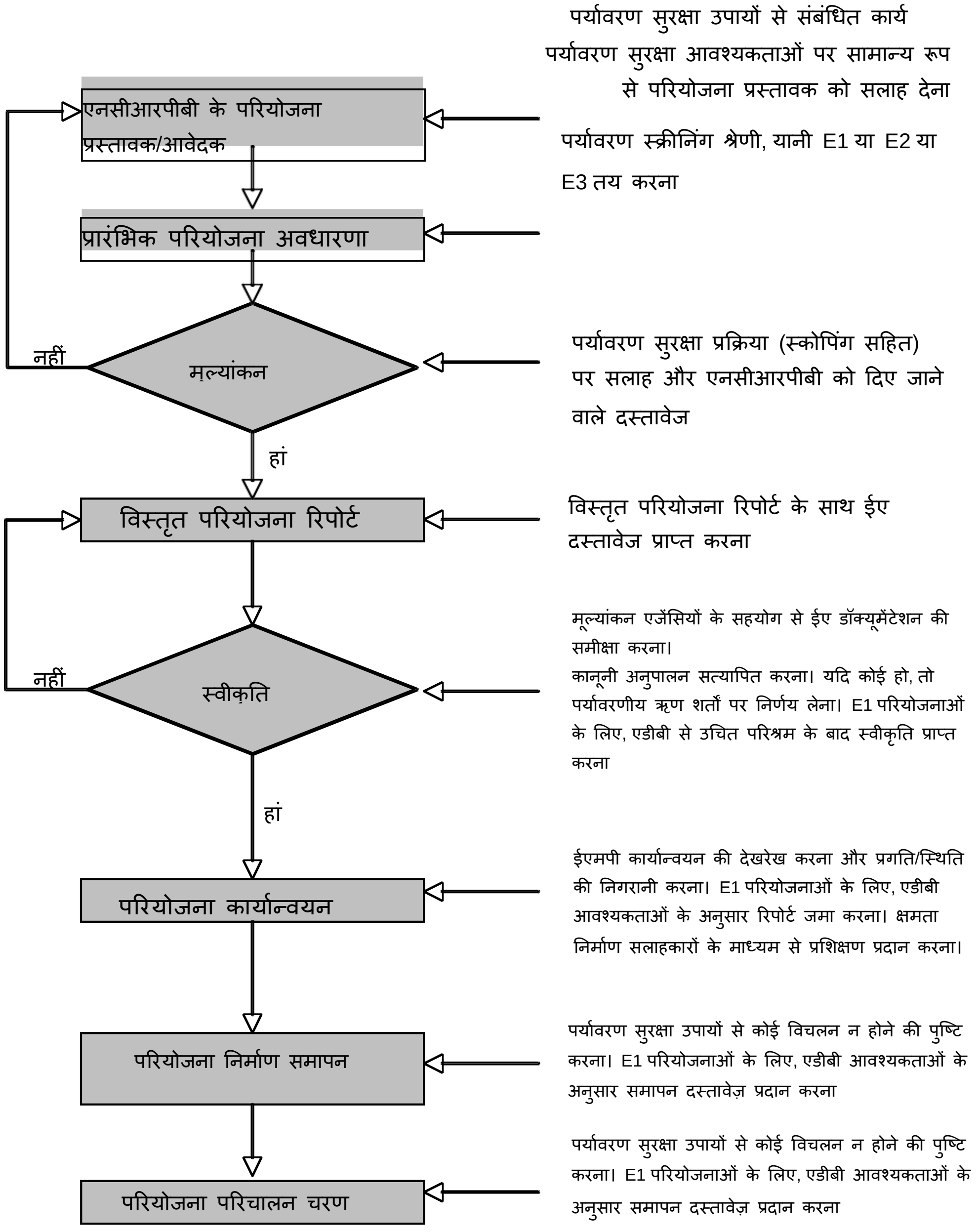

एडीबी = एशियाई विकास बैंक, ईए = निष्पादन एजेंसी, ईएमपी = पर्यावरण प्रबंधन योजना, एनसीआरपीबी = राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,

86. उपरोक्त प्रवाह चार्ट इंगित करता है कि दाता E1 परियोजनाओं के लिए अपना ड्यू डिलिजेंस करेगा क्योंकि इन्हें डोनर वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी A परियोजनाओं के रूप में माना जाएगा। अपने उचित परिश्रम के भाग के रूप में, डोनर (i) वित्तीय मध्यस्थ द्वारा एकत्र की गई पर्यावरणीय जानकारी की समीक्षा करेगा, (ii) आवश्यक अतिरिक्त जानकारी निर्धारित करेगा, (iii) उचित शमन उपायों को निर्धारित करने में सहायता करेगा और (iv) शर्तों को निर्दिष्ट करेगा जिसके तहत परियोजनाएं आगे बढ़ सकती हैं।

इन परियोजनाओं के लिए, डोनर परियोजना की मंजूरी से पहले ईआईए को मंजूरी देगा और एनसीआरपीबी/डोनर यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना की मंजूरी से कम से कम 120 दिन पहले ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाए।

87. एनसीआरपीबी पर्यावरण मूल्यांकन के संचालन और अनुदान निधि के तहत ईआईए/आईईई और ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा जो एडीबी क्रेडिट लाइन के माध्यम से उपलब्ध है।

88. पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आवश्यक मुख्य दस्तावेज इस प्रकार हैं:

<u>E1 परियोजनाएं:</u>

(i) पूर्ण पर्यावरण सूचना स्क्रीनिंग प्रारूप: यह सूचना के लिए एक पेज का अनुरोध है जिसे एनसीआरपीबी मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसके लिए एनसीआरपीबी वर्गीकरण के आधार पर परियोजना को वर्गीकृत करने के लिए प्रथम स्तर की जानकारी की आवश्यकता होती है जो मूल्यांकन प्रक्रिया और दस्तावेजों की पहचान करने में मदद करेगी जो परियोजना प्रस्तावक/आईए को देने की जरुरत होगी।

(ii) विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट: परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने के लिए ईआईए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यवहार्यता के हिस्से के रूप में परियोजना नियोजन चरण के रूप में जल्द से जल्द ईआईए किया जाएगा, इस प्रकार यह आश्वासन दिया जा सकता है कि परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होगी। परियोजना से पर्यावरणीय प्रभावों के संभावित महत्व के कारण ईआईए को गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। ईआईए की मांग: (a) संभावित प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों की स्क्रीनिंग और स्कूपिंग, (b) ईआईए के संदर्भ की शर्तों पर एमओईएफ/राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और/या एनसीआरपीबी/एडीबी से सहमत होना, (c) संभावित प्रभावों का व्यापक विश्लेषण; (d) व्यावहारिक शमन उपायों को तैयार करने के लिए किए जाने वाले कार्य; (e) स्क्रीन पर प्रभाव का गहन आर्थिक मूल्यांकन और सर्वोत्तम विकल्प का मूल्यांकन; और (f) पर्याप्त पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए गहन विश्लेषण। ईआईए अध्ययन करने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं: (a) परियोजना क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का वर्णन, (b) संभावित प्रभाव का आकलन, (c) शमन उपाय तैयार करना, और (d) पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना। ईआईए रिपोर्ट में निम्नलिखित संरचना में इसकी सामग्री शामिल होगी: (a) परिचय, (b) परियोजना का विवरण, (c) पर्यावरण का विवरण, (d) विकल्प, (e) प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय, (f)) आर्थिक आकलन, (g) पर्यावरण प्रबंधन योजना, (h) सार्वजनिक भागीदारी और प्रकटीकरण और (i) निष्कर्ष।

(iii) कार्यकारी सारांश ईआईए रिपोर्ट: एक कार्यकारी सारांश ईआईए रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत की जाएगी जो डोनर को देने और जनता को दिखाने के लिए एक अकेला दस्तावेज हो सकता है।

(iv) (iv) पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी): पर्यावरण प्रबंधन में पर्यावरण संरक्षण और शमन उपायों के कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी शामिल है। पर्यावरण संरक्षण उपाय (a) पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए किए जाते हैं, (b) खोए हुए पर्यावरणीय संसाधनों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं, या (c) पर्यावरणीय संसाधनों को बढ़ाते हैं। ये उपाय आमतौर पर ईएमपी में निर्धारित किए जाते हैं, जो परियोजना के सभी चरणों को पूर्व-निर्माण से डीकमीशनिंग तक कवर करता है और शमन और अन्य उपायों की रूपरेखा तैयार करता है जो पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने या समाप्त करने के लिए किए जाएंगे (निम्नलिखित तालिका देखें) ईएमपी में पर्यावरण ऋण अनुबंधों के लिए प्रस्तावित वस्तुओं और उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित परियोजना की सिफारिश करने के प्रस्ताव को भी शामिल किया जाएगा। ईएमपी की विशिष्ट सामग्री में शामिल होंगे

(a) संभावित प्रभावों का सारांश, (b) नियोजित शमन उपायों का विवरण, (c) नियोजित पर्यावरणीय निगरानी का विवरण, (d) नियोजित सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का विवरण, (e) शमन उपायों और निगरानी आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारियों और प्राधिकरणों का विवरण, (f) रिपोर्टिंग और समीक्षा के लिए जिम्मेदारियों का विवरण, (g) स्टाफिंग चार्ट सहित कार्य योजना, परियोजना टीम के विभिन्न सदस्यों द्वारा भागीदारी के प्रस्तावित कार्यक्रम और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की गतिविधियाँ और इनपुट (h) पर्यावरणीय उत्तरदायी खरीद योजना और (i) विस्तृत लागत अनुमान

(v) शर्तों के साथ एमओईएफ की पर्यावरणीय मंजूरी, यदि कोई हो: E1 परियोजनाओं के लिए (जो एमओईएफ के अनुसार A हैं), एमओईएफ परियोजना की समीक्षा करेगा और प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक विस्तृत ईआईए के लिए संदर्भ की शर्तें- प्रदान करेगा। एमओईएफ के संदर्भ की शर्तें ऊपर उल्लिखित ईआईए के साथ एकीकृत की जाएंगी और एक विस्तृत ईआईए दस्तावेज तैयार किया जाएगा। एक बार विस्तृत ईआईए तैयार और जमा हो जाने के बाद, एमओईएफ समीक्षा करेगा और अपनी पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करेगा। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद, परियोजना प्रस्तावक/आईए को शर्तों, यदि कोई हो, के साथ मंजूरी पत्र की प्रति जमा करनी होगी।

E2 परियोजनाएं:

(i) पूर्ण पर्यावरण सूचना स्क्रीनिंग प्रारूप: यह सूचना के लिए एक पेज का अनुरोध है जिसे एनसीआरपीबी मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसके लिए एनसीआरपीबी श्रेणी के अनुसार परियोजना को वर्गीकृत करने के लिए प्रथम स्तर की जानकारी की आवश्यकता होती है जो मूल्यांकन प्रक्रिया और दस्तावेजों की पहचान करने में मदद करेगी जो परियोजना प्रस्तावक/आईए को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

(ii) प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षण (आईईई): परियोजना स्तर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को शामिल करने के लिए आईईई एक महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यवहार्यता के हिस्से के रूप में आईईई को परियोजना नियोजन चरण के रूप में जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, इस प्रकार यह आश्वासन दिया जा सकता है कि परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होगी आईईई अध्ययन करने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं: (a) परियोजना क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का वर्णन करना, (b) संभावित प्रभावों का आकलन करना, (c) शमन उपाय तैयार करना और (d) संस्थागत आवश्यकताओं और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना। आईईई रिपोर्ट में निम्नलिखित संरचना होगी: (a) परिचय, (b) परियोजना का विवरण, (c) पर्यावरण का विवरण, (d) संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और शमन उपायों की स्क्रीनिंग, (e) संस्थागत आवश्यकताएं और पर्यावरण प्रबंधन योजना, (f) सार्वजनिक परामर्श और सूचना प्रकटीकरण, (g) निष्कर्ष और सिफारिश और (h) निष्कर्ष। आईईई का निष्कर्ष है कि परियोजना का कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होगा, तो पर्यावरणीय मूल्यांकन को पूर्ण माना जाता है।

(iii) शर्तों के साथ राज्य-स्तरीय पर्यावरणीय मंजूरी, यदि कोई हो: E2 परियोजनाओं के लिए (जो कि एमओईएफ के अनुसार B1 या B2 हैं), संबंधित एसईआईएए और इसकी विशेषज्ञ/तकनीकी मूल्यांकन समिति परियोजना की समीक्षा करेगी और एक दायरा प्रदान करेगी। संदर्भ-सीमित ईआईए के लिए या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक प्रश्नावली प्रदान करें। यदि एक सीमित ईआईए की आवश्यकता है, तो एसईआईएए की संदर्भ की शर्तें आईईई के साथ एकीकृत की जाएंगी और एक आईईई/सीमित ईआईए दस्तावेज तैयार किया जाएगा। एक बार सीमित ईआईए या पूर्ण प्रश्नावली तैयार और जमा हो जाने के बाद, एसईआईएए समीक्षा करेगा और अपनी पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करेगा। एक बार प्राप्त होने के बाद, परियोजना प्रस्तावक/आईए को शर्तों के साथ मंजूरी पत्र की प्रति जमा करनी होगी। कुछ E2 परियोजनाओं के लिए, एमओईएफ स्तर पर या एसईआईएए स्तर पर कोई मंजूरी आवश्यक नहीं है।

2. सामाजिक

89. ओवरले के रूप में सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ एनसीआरपीबी का परियोजना चक्र नीचे फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है।

फ्लो चार्ट: परियोजना चक्र और सामाजिक सुरक्षा

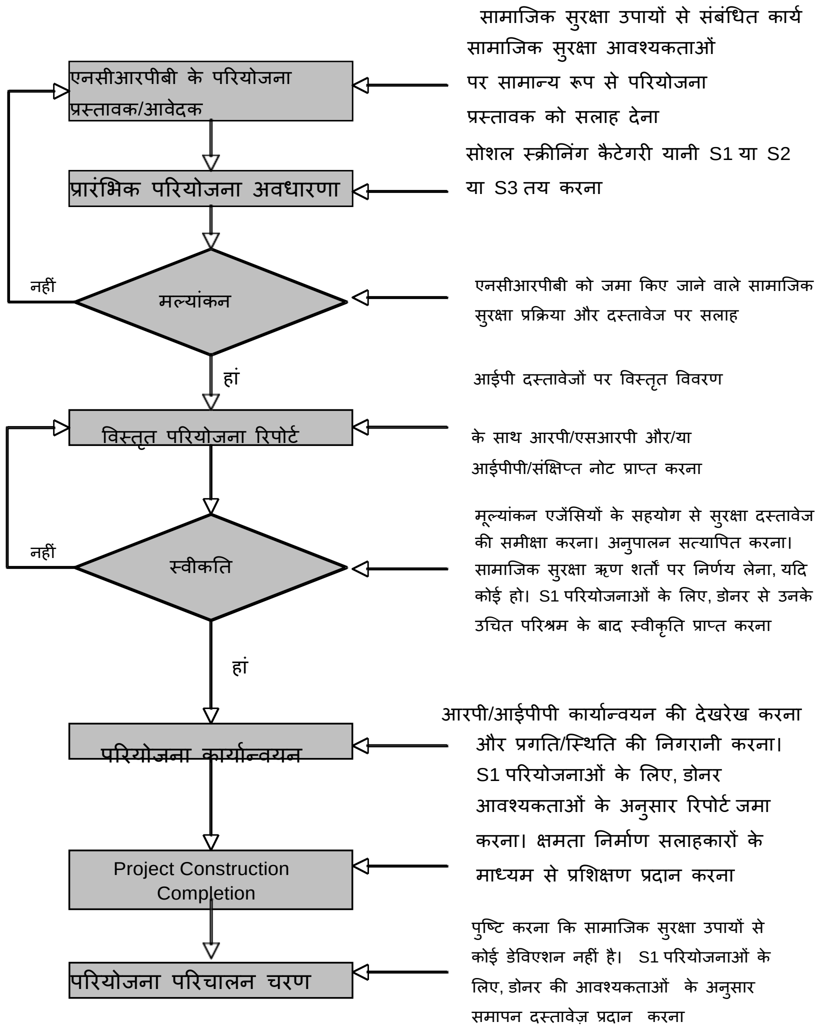

आईपीपी = स्थानीय लोग योजना, आरपी = पुनर्वास योजना, एसआरपी = लघु पुनर्वास योजना,

90. उपरोक्त प्रवाह चार्ट इंगित करता है कि डोनर S1 परियोजनाओं के लिए उचित परिश्रम करेगा क्योंकि वे डोनर के वर्गीकरण के आधार पर श्रेणी A की परियोजनाएँ हैं। इसके उचित परिश्रम के हिस्से के रूप में, डोनर (i) वित्तीय मध्यस्थ द्वारा एकत्र की गई सामाजिक जानकारी की समीक्षा करेगा, (ii) आवश्यक किसी भी अतिरिक्त जानकारी का निर्धारण, (iii) उपयुक्त शमन उपायों को निर्धारित करने में सहायता और (iv) शर्तों को निर्दिष्ट करें जिसके तहत परियोजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए, दाता परियोजना अनुमोदन से पहले आरपी और/या आईपीपी, यदि लागू हो, को मंजूरी देगा। एनसीआरपीबी/डोनर यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के अनुमोदन से पहले ड्राफ्ट आरपी और/या आईपीपी उपलब्ध कराया जाए।

91. एनसीआरपीबी उपलब्ध अनुदान निधि के तहत सामाजिक मूल्यांकन/अध्ययन के संचालन और आरपी और आईपीपी रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा।

92. एनसीआरपीबी को परियोजनाओं को जमा करते समय और कार्यान्वयन के दौरान सामाजिक मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आवश्यक मुख्य दस्तावेज निम्नानुसार हैं:

<u>S1 परियोजनएं</u>

- पूर्ण सामाजिक सूचना स्क्रीनिंग प्रारूप: यह जानकारी के लिए एक पेज का अनुरोध है जिसे एनसीआरपीबी मूल्यांकन प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में जमा करने की आवश्यकता है। इसके लिए एनसीआरपीबी श्रेणी के अनुसार परियोजना को वर्गीकृत करने के लिए प्रथम स्तर की जानकारी की आवश्यकता होती है जो मूल्यांकन प्रक्रिया और दस्तावेजों की पहचान करने में मदद करेगी जो परियोजना प्रस्तावक/आईए को देने की जरुरत होगी।
- पुनर्वास योजना और/या स्थानीय लोग योजना: पुनर्वास योजना और स्थानीय लोगों की योजना को डीपीआर के साथ एनसीआरपीबी को देने की जरुरत है। आरपी और/या आईपीपी को मंजूरी देने पर एनसीआरपीबी इसे समीक्षा के लिए डोनर को भेजेगा और एक बार डोनर की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना प्रस्तावक/आईए को इन्हें लागू करने की सलाह देगा।
- निगरानी रिपोर्ट: परियोजना प्रस्तावक/आईए एनसीआरपीबी को दिए गए प्रारूप में मासिक प्रगति रिपोर्ट देगा। एस-1 परियोजनाओं के लिए निगरानी बाहरी विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी जो मासिक प्रगति रिपोर्ट और एक वार्षिक/अंतिम निगरानी और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इसे डोनर को भेजा जाएगा।

<u>S2 परियोजनएं</u>

- पूर्ण सामाजिक सूचना स्क्रीनिंग प्रारूप: यह सूचना के लिए एक पेज का अनुरोध है जिसे एनसीआरपीबी मूल्यांकन प्रक्रिया के शुरूआती चरणों में देने की जरुरत होती है। इसके लिए एनसीआरपीबी श्रेणी के अनुसार परियोजना को वर्गीकृत करने के लिए प्रथम स्तर की जानकारी की जरुरत होती है जो मूल्यांकन प्रक्रिया और दस्तावेजों की पहचान करने में मदद करेगी जो परियोजना प्रस्तावक/आईए को देने की जरुरत होगी।
- लघु पुनर्वास योजना और/या लघु आईपीपी: डीपीआर के साथ एनसीआरपीबी को एक लघु आरपी और/या आईपीपी जमा करने की आवश्यकता है। लघु योजनाओं में पूर्ण योजनाएँ तैयार करने के लिए रूपरेखा में सूचीबद्ध सभी मुद्दों को कम विवरण में शामिल किया जाएगा।
- निगरानी रिपोर्ट: आईए एनसीआरपीबी को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगा।

<u>S3 परियोजनएं</u>

- पूर्ण सामाजिक सूचना स्क्रीनिंग प्रारूप: यह जानकारी के लिए एक पेज का अनुरोध है जिसे एनसीआरपीबी मूल्यांकन प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में जमा करने की जरुरत है। इसके लिए एनसीआरपीबी श्रेणी के अनुसार परियोजना को वर्गीकृत करने के लिए प्रथम स्तर की जानकारी की जरुरत होती है जो मूल्यांकन प्रक्रिया और दस्तावेजों की पहचान करने में मदद करेगी जो परियोजना प्रस्तावक/आईए को देने की जरुरत होगी।

परियोजना चक्र में आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, एनसीआरपीबी मानक फॉर्म/फॉर्मेट/प्रोफॉर्मा का इस्तेमाल करेगा।

D. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

93. यह सुरक्षा आवश्यकताओं पर परियोजना प्रस्तावकों/आईए, उनके सलाहकारों और ठेकेदारों को प्रशिक्षित करने और क्षमता निर्माण करने की प्रक्रिया है। यह सर्वविदित है कि उनकी सुरक्षा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना होगा। इस क्षमता की कमी को दूर करने के लिए, एनसीआरपीबी अपने परियोजना प्रस्तावकों/आईए के साथ इस क्षमता के निर्माण में नेतृत्व की भूमिका निभाएगा।

एनसीआरपीबी अपने ईएसएमएस कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को पूरी तरह से पहचानता है जो परियोजना प्रस्तावक/आईए के सुरक्षा उपायों के प्रदर्शन पर निर्भर है।

94. एनसीआरपीबी परियोजना प्रस्तावकों/आईए, सलाहकारों और ठेकेदारों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाहरी क्षमता निर्माण सलाहकारों को नियुक्त करेगा। ये लगभग एक दिवसीय लघु प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से निम्नलिखित को कवर करेगा:

- पर्यावरण और सामाजिक (भूमि अधिग्रहण, आईआर और आईपी) मुद्दे जो परियोजना का सामना कर रहे हैं।
- कानूनी आवश्यकताएं जिनका पालन करना आवश्यक है, उदाहरण पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तें और एनआरआरपी की पात्रताओं का पालन।
- एनसीआरपीबी का ईएसएमएस और क्षमता निर्माण में इसकी भूमिका।
- पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन जैसे कि ईआईए, आईईईई और एसआईए।
- संबंधित ईएमपी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (आरपी और आईपीपी) में निर्धारित प्रबंधन उपाय।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य पर्यावरण और अच्छे सामाजिक कार्य।

95. सुरक्षा उपाय क्षमता निर्माण सलाहकार, एनसीआरपीबी के निर्णयकर्ताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सामान्य प्रशिक्षण भी आयोजित करेंगे, जिसमें रसुरक्षा उपाय के मुद्दों को इसके वित्तपोषण निर्णयों और ऋण वितरण प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने की जरुरत होगी।

E. निगरानी और रिपोर्टिंग

96. यह प्रक्रिया एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की सुरक्षा आवश्यकताओं के कार्यान्वयन अनुपालन की निगरानी के लिए है।

97. अपनी आंतरिक समीक्षा बैठकों के एक भाग के रूप में, एनसीआरपीबी जांच करता है कि संभावित परियोजना प्रस्तावकों/आईए, परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रगति रिपोर्ट की निगरानी और साइट सत्यापन जब भी ये किए जाते हैं, के साथ बातचीत में आंतरिक रूप से ईएसएमएस का पालन किया जा रहा है।

98. एनसीआरपीबी उन सभी परियोजनाओं की निगरानी करेगा जिन्हें यह निर्माण, संचालन और रखरखाव के दौरान सुरक्षा आवश्यकताओं की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए वित्तपोषित करता है। परियोजना प्रस्तावक/आईए समीक्षा के लिए एनसीआरपीबी को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। एनसीआरपीबी आवश्यक होने पर परियोजना स्थलों का दौरा करता है। प्रगति रिपोर्ट के सत्यापन, क्षेत्र के दौरे और ऋण वितरण शर्तों के अनुपालन (कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन सहित) के आधार पर, बाद में वितरित किए जाते हैं।

99. समय-समय पर, एनसीआरपीबी वित्तपोषित सभी परियोजनाओं की एक समेकित प्रगति रिपोर्ट संकलित करेगा। इस समेकित रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में, कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक प्रमुख/महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की पहचान की जाएगी और की जा रही/की जाने वाली कार्रवाई की स्पष्ट रूप से पहचान की जाएगी। एनसीआरपीबी निगरानी रिपोर्ट में पहचाने गए मुद्दों के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई पर संबंधित परियोजना प्रस्तावकों/आईए को सूचित करेगा।

100. सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए विशिष्ट, परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में सामाजिक सुरक्षा उपायों के संबंध में सहमत शर्तों के अनुपालन की निगरानी और मूल्यांकन करना सुरक्षा अधिकारी का कार्य है। यह सीधे तौर पर या काम पर रखी गई निगरानी और मूल्यांकन एजेंसियों की मदद से किया जा सकता है। प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- परियोजना प्रस्तावक/आईए एनसीआरपीबी को सामाजिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट भेजते हैं। सुरक्षा अधिकारी ऋण अनुबंध/समझौते में सहमत माइलस्टोन के आधार पर ऐसी रिपोर्ट का मूल्यांकन करता है।

- सुरक्षा उपाय अधिकारी आवश्यकतानुसार तिमाही रिपोर्ट की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र का दौरा करेंगे।
- यदि कार्यान्वयन में ढिलाई की गयी है, तो सुरक्षा अधिकारी एनसीआरपीबी के वित्तीय निर्णयों के साथ समन्वय करेंगे ताकि अनुपालन होने तक संवितरण रोके जा सकें।
- अगर परियोजना प्रस्तावक/आईए की ओर से बार-बार और प्रलेखित चेतावनियों के बाद भी इस संबंध में लगातार चूक होती है, तो एनसीआरपीबी के वित्त पोषण अधिकारियों को आगे किसी भी संवितरण को रोकने और ऋण को रद्द करने की सलाह दी जा सकती है।
- कार्यान्वयन के अंतिम परिणाम को देखने के लिए परियोजना का अंतिम मूल्यांकन होना चाहिए। इस मूल्यांकन से मिले सबक को परियोजना प्रस्तावक/आईए के साथ साझा किया जाना चाहिए और एनसीआरपीबी के सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

101. E1 और S1 परियोजनाओं के लिए, निगरानी और मूल्यांकन बाहरी योग्य और अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। उनकी अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट डोनर और एनसीआरपीबी को उनकी अनुपालन आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में दी जाएगी।

102. एनसीआरपीबी E1 और S1 परियोजनाओं के लिए डोनर की आवधिक निगरानी और पर्यवेक्षण में मदद करेगा।

103. एनसीआरपीबी ईएसएमएस के कार्यान्वयन की स्थिति पर कम से कम सालाना आवधिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। यदि रिपोर्ट या दाता की समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि ईएसएमएस काम नहीं कर रहा है, तो एनसीआरपीबी एक सुधारात्मक कार्य योजना तैयार करेगा, दाता से सहमत होगा और योजना को लागू करेगा।

F. ईएसएमएस ऑडिट प्रक्रिया

104. एनसीआरपीबी के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों और इसके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का एक स्वतंत्र मूल्यांकन होगा। इसके लिए, एनसीआरपीबी के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की वार्षिक स्वतंत्र लेखा परीक्षा शामिल है।

105. यह ईएसएमएस ऑडिट भी होगा:

- सभी प्रासंगिक सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों और इसके व्यवसाय और संचालन के प्रभावों को प्रबंधित करने और संबोधित करने के लिए ग्राहक की क्षमता का आकलन करना, विशेष रूप से, डोनर की सुरक्षा आवश्यकताओं में पहचाने गए मुद्दे;
- अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मेजबान देश के दायित्वों को लागू करने वाले कानूनों सहित पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित क्षेत्राधिकारों के लागू कानूनों और विनियमों के साथ ग्राहक के अनुपालन रिकॉर्ड का आकलन करना जिसमें परियोजना संचालित होती है; और
- एनसीआरपीबी और उसके परियोजना प्रस्तावक के मुख्य हितधारक समूहों और वर्तमान हितधारक संलग्नता गतिविधियों की पहचान करना।

106. यह ईएसएमएस ऑडिट एनसीआरपीबी द्वारा कार्यान्वयन के तहत ईएसएमएस और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन के कार्यान्वयन के लिए चयनित परियोजनाओं दोनों को कवर करेगा।

107. एनसीआरपीबी हर साल एक ईएसएमएस ऑडिट करेगा।

108. बाहरी और स्वतंत्र संसाधन व्यक्तियों की पहचान ईएसएमएस लेखा परीक्षकों के रूप में की जाएगी और वे इस लेखापरीक्षा का कार्य करेंगे। ईएसएमएस लेखापरीक्षकों के पास प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा के साथ-साथ निवेश परियोजनाओं के लेखापरीक्षा दोनों करने का अनुभव होगा। प्रतिष्ठित प्रत्यायन निकायों द्वारा लेखापरीक्षकों के रूप में प्रमाणित व्यक्तियों या एजेंसियों के रूप में संसाधन व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा।

एनसीआरपीबी यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट टीम के पास पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर ऑडिटिंग और विषय ज्ञान/अनुभव दोनों की अच्छी जानकारी हो।

109. आंतरिक कर्मचारियों/डिवीजन की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की भर्ती में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। एनसीआरपीबी का निदेशक मंडल सीधे नियुक्तियां करेगा। स्वतंत्र लेखापरीक्षक भी निदेशक मंडल को सीधे रिपोर्ट (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जमा करते हुए) करेगा। यह अनिवार्य होगा कि आंतरिक कर्मचारी/प्रभाग लेखापरीक्षक को अपनी गतिविधियों के बारे में आवश्यक जानकारी दे। दिए गए वर्ष में एनसीआरपीबी द्वारा संचालित पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों (परियोजनाओं की संख्या, आदि) की सीमा के आधार पर लेखा परीक्षक का शुल्क तय किया जा सकता है।

110. वे सभी परियोजनाएँ जिन्हें उच्च प्रभाव के लिए वर्गीकृत किया गया है, यानी E1 और S1, इन ऑडिट में कवर की जाएंगी, जब तक कि वर्तमान या पिछले वर्ष में संवितरण किया गया हो।

111. शेष परियोजनाओं के लिए, लगभग 25% अन्य परियोजनाओं का चयन किया जाएगा, इसमें दाता-वित्त पोषित परियोजनाएं शामिल होंगी, और विभिन्न परियोजना प्रकारों से कम से कम एक परियोजना शामिल होगी।

112. एनसीआरपीबी और संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आईए ईएसएमएस लेखा परीक्षकों को उचित समर्थन और सहयोग प्रदान करेंगे।

113. ईएसएमएस लेखा परीक्षक एनसीआरपीबी और परियोजना प्रस्तावक/आईए के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एनसीआरपीबी प्रत्येक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई पर सहमत होगा और अनुवर्ती कार्रवाइयों को लागू करने के लिए एक समय सीमा पर सहमत होगा।

114. ईएसएमएस लेखा परीक्षक यह पुष्टि करने के लिए एक डेस्क समीक्षा करेंगे कि अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। इस पुष्टि के प्राप्त होने के बाद ही वार्षिक लेखापरीक्षा समाप्त मानी जाएगी।

G. सूचना प्रकटीकरण और शिकायत निवारण प्रक्रिया

115. एनसीआरपीबी अपनी वेबसाइट पर सभी पर्यावरणीय और सामाजिक सूचनाओं का खुलासा करेगा। इसमें ईएसएमएस और सभी पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन दस्तावेज़ और योजनाएँ और उन परियोजनाओं की निगरानी/प्रगति रिपोर्ट शामिल होंगी जिनके लिए यह धन उपलब्ध कराता है। डोनर की सार्वजनिक संचार नीति के अनुरूप, एनसीआरपीबी यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों के बारे में प्रासंगिक जानकारी समयबद्ध तरीके से, सुलभ स्थान पर और प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों के लिए समझने योग्य रूप और भाषा में उपलब्ध कराई जाए। आम जनता सहित, ताकि वे परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में सार्थक इनपुट प्रदान कर सकें। श्रेणी E1/S1 परियोजनाओं के लिए, डोनर की विशेष सूचना प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अतिरिक्त रूप से पूरा करना होगा। ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट परियोजना अनुमोदन से कम से कम 120 दिन पहले डोनर को और परियोजना अनुमोदन से पहले आरपी और आईपीपी को प्रस्तुत की जाएगी।

116. एनसीआरपीबी प्रत्येक परियोजना प्रस्तावक/आईए के लिए यह शर्त भी रखेगा कि वे अपनी वेबसाइट पर पर्यावरण और सामाजिक आकलन और योजनाओं का खुलासा करें। इसके अलावा, परियोजना प्रस्तावक/आईए इसे अनुरोध पर उपलब्ध कराएंगे।

117. किसी भी हितधारक शिकायत या प्रश्न या अधिक जानकारी के अनुरोध के मामले में, प्रक्रिया के मामले में, एनसीआरपीबी परियोजना प्रस्तावकों/आईए से अनुरोध करेगा कि वे प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जवाब दें। यदि पूछताछ उसकी ईएसएमएस गतिविधियों/संचालन/कार्यप्रणाली से संबंधित है तो एनसीआरपीबी ऐसा ही करेगा। परियोजना स्तर पर, शिकायत निवारण ईआईए/आईईई/आरपी/आईपीपी के अनुसार होगा।

V. संगठनात्मक व्यवस्था

A. विभिन्न संगठनों की भूमिकाएँ

1. एनसीआरपीबी

118. एनसीआरपीबी मूल्यांकन से पहले और एनसीआरपीबी मूल्यांकन के दौरान पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। एक बार परियोजना जमा हो जाने के बाद, एनसीआरपीबी वित्त पोषण के लिए संपर्क की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा। इसमें पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मूल्यांकन शामिल होगा और यह समग्र मूल्यांकन का एक हिस्सा होगा जिसमें तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक पहलू भी शामिल होंगे। इसी मूल्यांकन के आधार पर एनसीआरपीबी ऋण स्वीकृत करता है।

2. मूल्यांकन एजेंसियां

119. मूल्यांकन एजेंसियों ("राष्ट्रीय संस्थानों" के रूप में जाना जाता है) की पहचान तकनीकी व्यवहार्यता, लागत उचितता, वित्तीय व्यवहार्यता और अच्छी इंजीनियरिंग डिजाइन, अनिवार्य मंजूरी की स्थिति आदि के संबंध में डीपीआर का विस्तृत मूल्यांकन करने और परियोजना मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए की जाएगी। इसकी समीक्षा के लिए एनसीआरपीबी को रिपोर्ट करें। मूल्यांकन एजेंसियां आवश्यकता के आधार पर परियोजना के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं पर भी गौर करेंगी, ताकि यह जांच की जा सके कि यह एनसीआरपीबी के ईएसएमएस का अनुपालन करती है या नहीं। एनसीआरपीबी यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन एजेंसियों के पास पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने में आवश्यक विशेषज्ञता हो। मूल्यांकन एजेंसियों में निम्न संगठन शामिल होंगे जैसे:

- जल और विद्युत परामर्श सेवाएं (वैपकोस): बिजली, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल): बिजली, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भूमि विकास, औद्योगिक नगर, लैंडस्केपिंग, आईटी पार्क, परिवहन, अनौपचारिक क्षेत्र
- राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई): जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी): भूमि विकास, सामाजिक अवसंरचना, आईटी पार्क, अनौपचारिक क्षेत्र
- भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी): भूमि विकास, सामाजिक बुनियादी ढांचा
- एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड: भूमि विकास, सामाजिक बुनियादी ढांचा
- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई): परिवहन

3. परियोजना प्रस्तावक/कार्यान्वयन एजेंसियां (आईएएस)

120. परियोजना प्रस्तावक/आईए, जो वित्त पोषण के लिए एनसीआरपीबी से संपर्क करता है, लाइन विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों और औद्योगिक विकास निगमों आदि सहित एनसीआर प्रतिभागी राज्य सरकारों की कोई भी एजेंसी हो सकती है। परियोजना प्रस्तावक/आईए कार्यान्वयन के लिए एनसीआरपीबी के वित्तपोषण के लिए परियोजना और दृष्टिकोण तैयार करता है। आवश्यक परियोजना प्रलेखन (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावकों/आईए की है। परियोजना प्रस्तावक/आईए आमतौर पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करते हैं और डीपीआर तैयार करते हैं। इसी तरह, आवश्यक दस्तावेज तैयार करने और एनसीआरपीबी के पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए परियोजना प्रस्तावक/आईए की जिम्मेदारी होगी।

4. डिजाइन सलाहकार

121. इन-हाउस क्षमता की कमी के कारण, परियोजना प्रस्तावक/आईए आमतौर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त करते हैं। कुछ संगठन, विशेष रूप से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) जैसे राज्य लाइन विभाग भी परामर्शदाताओं की सीमित सहायता के या इनके बिना इन कार्यों को इन-हाउस करते हैं। डिजाइन सलाहकार परियोजना प्रस्तावक/आईए को आवश्यकतानुसार सुरक्षा दस्तावेज तैयार करने में भी सहायता करेंगे और आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे। इन डिजाइन सलाहकारों को इस ईएसएमएस में दिए गए एनसीआरपीबी की सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि वे डिजाइन चरण के दौरान आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

5. निर्माण ठेकेदार

122. परियोजना प्रस्तावक/आईए बुनियादी ढांचा तत्वों के निर्माण के लिए निर्माण ठेकेदारों की नियुक्ति करते हैं। निर्माण ठेकेदारों के पास पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएं होंगी जिनका उन्हें अपने अनुबंध के एक हिस्से के रूप में पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, ईएमपी अनुबंध दस्तावेजों का एक हिस्सा बनेगा और ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईएमपी आवश्यकताओं का पालन किया जाए।

6. परियोजना प्रबंधन या पर्यवेक्षण सलाहकार (पीएमसी या एससी)

123. परियोजना प्रस्तावकों/आईए के संबंधित न्यायिक इंजीनियर साइट पर निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। इन इंजीनियरों को पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि निर्माण ठेकेदार इसका पालन करें। पर्यवेक्षण में आईएएस की सहायता के लिए जहां कहीं भी परियोजना प्रबंधन सलाहकार कार्यरत हैं, परियोजना प्रबंधन सलाहकारों के संबंधित अधिकारियों को पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा।

7. संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) एजेंसियां

124. आम तौर पर, आइए अपने स्वयं के कर्मचारियों या संविदात्मक कर्मचारियों के माध्यम से बुनियादी ढांचे का संचालन और रखरखाव करते हैं। इन कर्मचारियों को परिचालन चरण में पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के बारे में सूचित किया जाएगा और संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आईए यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

B. संगठनात्मक संरचना

125. पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए एनसीआरपीबी में एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन सेल (ईएसएमसी) होगा। ईएसएमसी को एनसीआरपीबी के मूल्यांकन कार्य के अंदर रखा जाएगा और इसके दो अलग-अलग उप-कार्य, अर्थात् पर्यावरण सुरक्षा उपायों और सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रबंधन होंगे।

126. ईएसएमसी में, एक पूर्णकालिक अलग कर्मचारी, एक सुरक्षा अधिकारी होगा, जो सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को देखेगा। वह पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा कार्यों दोनों के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

127. यह सुरक्षा अधिकारी परियोजना प्रस्तावकों/आईए के साथ मिलकर काम करेगा जो दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन पहलुओं और संबद्ध सुरक्षा अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा उपायों पर एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के पोर्टफोलियो की निगरानी करेंगे और सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों/आईए के साथ काम करेंगे। सुरक्षा अधिकारी वार्षिक आधार पर एक ईएसएमएस लेखा परीक्षक को नियुक्त करेगा और E-1 और S-1 परियोजनाओं के लिए निगरानी और मूल्यांकन विशेषज्ञों की सेवाएं भी शामिल करेगा।

सुरक्षा अधिकारी परियोजना प्रस्तावकों/आईए और उनसे जुड़ी एजेंसियों के लिए जागरूकता, ज्ञान और कौशल का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की पहल करने की व्यवस्था भी करेगा। इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए, सुरक्षा अधिकारी आवश्यकता के आधार पर बाहरी पर्यावरण और सामाजिक सलाहकारों को नियुक्त करेगा। विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, परियोजना के प्रस्तावक/आईए परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन चरणों के दौरान सुरक्षा पहलुओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए अपने स्वयं के सुरक्षा कर्मचारियों और सलाहकारों को नियुक्त करेंगे। आमतौर पर, परियोजना की तैयारी के दौरान, परियोजना प्रस्तावक/आईए पर्यावरण सलाहकारों को ईआईए और सामाजिक अध्ययन करने के लिए नियुक्त करते हैं, ताकि एमओईएफ/एसईआईएए से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए ईएमपी और आरपी तैयार किया जा सके। कार्यान्वयन के दौरान, परियोजना प्रस्तावक / आईए अपने इंजीनियरों को पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपते हैं, जो परियोजना प्रबंधन सलाहकार के पर्यावरण इंजीनियर, ठेकेदार के पर्यावरण इंजीनियरों और आरपी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर सरकारी संगठन से निपटने के लिए मुख्य व्यक्ति होंगे।

128. सुरक्षा अधिकारी के पास विशेष रूप से निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और कार्य अनुभव होगा: योजना या पर्यावरण विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/सामाजिक विज्ञान या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ डिजाइन, समीक्षा और और डोनर-वित्तपोषित परियोजनाओं के एक भाग के रूप में सुरक्षा अनुपालन का मूल्यांकन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। इस पद के लिए मौजूदा एनसीआरपीबी कर्मचारियों पर भी विचार किया जा सकता है। उन्हें राष्ट्रीय कानूनी आवश्यकताओं के साथ-साथ डोनर आवश्यकताओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।

129. विभिन्न परियोजनाओं का सामना करने वाले सुरक्षा मुद्दों की श्रेणी को देखते हुए, सुरक्षा अधिकारी विशेष परियोजना की विशिष्ट जरूरतों/आवश्यकताओं के अनुरूप मामला-दर-मामला आधार पर बाहरी कंसलटेंट से विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे।

1. पर्यावरण

130. एनसीआरपीबी निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा उपायों से निपटेगा: इस ईएसएमएस की परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करना, वित्तपोषित परियोजनाओं की तुलना में विभिन्न अनुमतियों/मंजूरियों को प्राप्त करने के संदर्भ में कानूनी आवश्यकताओं की पुष्टि करना, उन शर्तों पर सलाह देना जो शामिल होंगी ऋण प्रसंविदाओं के एक भाग के रूप में, पर्यावरण प्रबंधन उपायों (जैसे ईएमपी) के कार्यान्वयन की निगरानी करना और आवधिक निगरानी और रिपोर्टिंग करना।

2. सामाजिक

131. एनसीआरपीबी ईएसएमसी की गतिविधियों के माध्यम से परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण, आईआर और आईपी मुद्दों के समस्याओं से निपटेगा। इनमें इस ईएसएमएस की परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करना, उन शर्तों पर सलाह देना शामिल है जिन्हें ऋण प्रसंविदाओं के एक भाग के रूप में शामिल किया जाएगा, यह पुष्टि करना कि भूमि अधिग्रहण और आरपी और आईपीपी जैसी योजनाएं सिविल कार्य शुरू होने से पहले पूरी हो गई हैं और आवधिक निगरानी और रिपोर्टिंग की गयी है।

132. संगठनात्मक व्यवस्थाओं को नीचे चार्ट में दिखाया गया है।

फ्लो चार्ट: ईएसएमएस संगठनात्मक संरचना

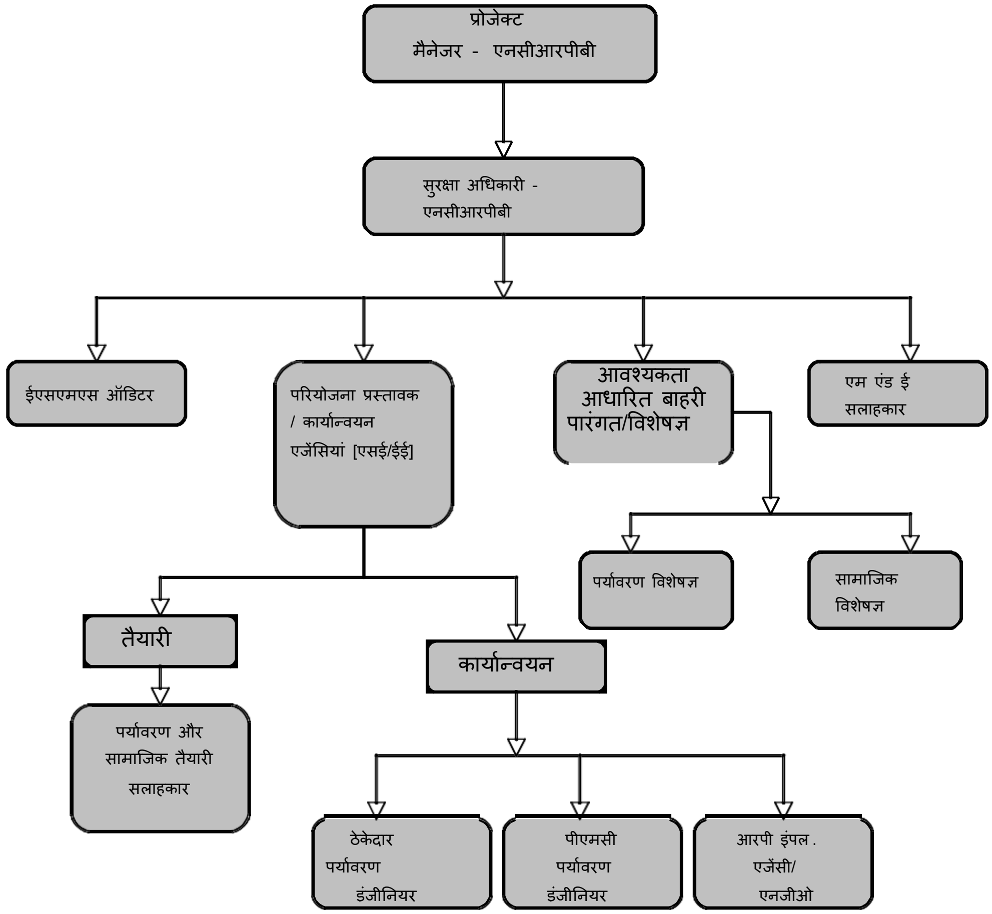

ईई = पर्यावरण विशेषज्ञ।, ईएसएमएस = पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली, एम एंड ई = निगरानी और मूल्यांकन, एनसीआरपीबी = राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, एनजीओ = गैर सरकारी संगठन, आरपी = पुनर्वास योजना, एसई = सामाजिक विशेषज्ञ

C. भूमिकाएँ, उत्तरदायित्व और अधिकार

1. पर्यावरण सुरक्षा कार्य

133. भूमिका इस ईएसएमएस की नीतियों और परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने की है, एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं के पर्यावरण सुरक्षा मुद्दों का जवाब देने के लिए और संभावित सुरक्षा मुद्दों की पहचान करने में भी सक्रिय है जो इसके परियोजनाओं की पोर्टफोलियो के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकते हैं।

134. पर्यावरण सुरक्षा कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित जिम्मेदारियां प्रासंगिक हैं:

- ईएसएमएस के पर्यावरणीय पहलुओं - पर्यावरणीय नीतियों और प्रक्रियाओं (स्क्रीनिंग, वर्गीकरण, पर्यावरण मूल्यांकन और अन्य) - को दिन-प्रतिदिन के आधार पर बनाए रखना और अपडेट रखना।
- पर्यावरण सुरक्षा उपायों पर एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के पोर्टफोलियो की निगरानी करना, निर्माण और परिचालन दोनों चरणों में समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करना और पर्यावरणीय सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईए के साथ काम करना।

- आईएएस और उनसे जुड़ी एजेंसियों के बारे में जागरूकता, ज्ञान और कौशल का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों में शामिल होना।
- डोनर एजेंसियों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- वार्षिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए बाहरी ईएसएमएस लेखापरीक्षकों को मदद और सहयोग प्रदान करना।
- एनसीआरपीबी की योजना प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी विचारों के एकीकरण पर परियोजना-स्तरीय अनुभवों का उपयोग करना और सलाह देना। यह पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को निर्धारित करने के माध्यम से किया जाना है और आवधिक निगरानी के माध्यम से पर्यावरणीय लक्ष्यों की परियोजना स्तर की उपलब्धियों ने पर्यावरणीय परिणामों में सुधार कैसे किया है।

135. पर्यावरण सुरक्षा कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार लोगों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

- दैनिक आधार पर ईएसएमएस कार्यान्वयन में सहायता के लिए एनसीआरपीबी के भीतर से प्रासंगिक जानकारी का अनुरोध करना।
- पर्यावरणीय सुरक्षा अनुपालन के संबंध में आईए से डेटा और दस्तावेज़ीकरण के लिए पूछें, उदाहरण कानूनी आवश्यकताओं या ईएमपी के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए निगरानी रिपोर्ट।
- एनसीआरपीबी मूल्यांकन और/या निगरानी टीमों को गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, वित्तपोषित परियोजनाओं में से किसी की किसी भी कानूनी आवश्यकताओं या पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन से संबंधित जोखिम के बारे में सूचित करना, जिससे एनसीआरपीबी उजागर होता है।
- एनसीआरपीबी मूल्यांकन टीम को पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के मुद्दों के अनुपालन न करने के कारण परियोजना पर वित्तपोषण निर्णय को स्थगित करने की सलाह देना।
- पर्यावरण सुरक्षा उपायों के मुद्दों का अनुपालन न करने के कारण परियोजना प्रस्तावक/आईए को किस्त के वितरण में देरी के लिए एनसीआरपीबी मूल्यांकन टीम को सलाह देना।

2. सामाजिक सुरक्षा कार्य

136. सुरक्षा अधिकारी की भूमिका एनसीआरपीबी को अपनी सामाजिक सुरक्षा नीति को कार्रवाई में बदलने में मदद करने की होगी।

137. सुरक्षा अधिकारी के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- समीक्षा करना कि क्या परियोजना प्रस्तावक/आईए ने पूर्व-नियोजन चरण के दौरान आईआर और आईपी पर पड़ने वाले प्रभावों से बचने या कम करने के प्रयास करना।
- यह सत्यापित करने के लिए परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीन कि क्या प्रभावों के महत्व के अनुरूप सुरक्षा दस्तावेज तैयार किए गए हैं और ऋण आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।
- सुनिश्चित करना कि परियोजना प्रस्तावक/आईए आईआर और आईपी के लिए योजना, परामर्श और प्रकटीकरण, आरपी और आईपीपी के कार्यान्वयन और शिकायत के निवारण सहित सामाजिक सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक योजना प्रक्रिया को पूरा करता है।
- सुनिश्चित करना कि एनसीआरपीबी का संवितरण निर्णय आरपी और आईपीपी कार्यान्वयन के सफल समापन को ध्यान में रखता है।
- सामाजिक सुरक्षा अनुबंधों को शामिल करने के लिए ऋण की शर्तें निर्धारित करना।
- आरपी और आईपीपी कार्यान्वयन पर प्रगति की आवधिक समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं।

- डोनरों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
- वार्षिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए बाहरी ईएसएमएस लेखापरीक्षकों को सामाजिक सुरक्षा उपायों पर मदद और सहयोग प्रदान करना।

138. सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

- सामाजिक सुरक्षा मुद्दों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक/आईए से अधिक जानकारी के लिए कॉल करना।
- एनसीआरपीबी को सलाह देना कि वह परियोजना प्रस्तावक/आईए से परियोजना प्रस्तावक/आईए द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन दस्तावेजों के सामाजिक सुरक्षा खंड पर फिर से काम करने के लिए कहना, उदाहरण डीपीआर।
- एनसीआरपीबी को सामाजिक सुरक्षा उपायों के मुद्दों का पालन न करने के कारण किसी परियोजना पर वित्तपोषण निर्णय को स्थगित करने की सलाह देना।
- एनसीआरपीबी को सामाजिक सुरक्षा मुद्दों का अनुपालन न करने के कारण परियोजना प्रस्तावक/आईए को किश्त के वितरण में देरी करने की सलाह देना।

D. बजटीय संसाधन

139. वार्षिक बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, एनसीआरपीबी यह सुनिश्चित करेगा कि ईएसएमएस की गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए और इसकी विभिन्न परियोजनाओं की तुलना में पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त धन/वित्त उपलब्ध कराया जाए।

140. निम्न तालिका एक वार्षिक सांकेतिक बजट प्रदान करती है:

तालिका 12: सांकेतिक बजट

क्र.सं.	विवरण	आधार	राशियां (रुपये मिलियन में)	धन के स्रोत
1.	सुरक्षा अधिकारी - वेतन बाहरी सुरक्षा	1 व्यक्ति, 40,000 रुपये प्रति माह	0.48	एनसीआरपीबी
2.	सलाहकार ईएसएमसी को सलाह देंगे [पीएमसी का हिस्सा]	4 व्यक्ति के लिए 2 सलाहकार, महीने प्रति वर्ष 250,000 रुपये प्रति माह (47 रुपये प्रति US$ पर US$ 5,000 प्रति माह)		क्रियान्वयन सहायता
3.	ड्यू डिलिजेंस / मूल्यांकन दौरे	प्रति माह 2 दौरे, 5,000 रुपये प्रति दौरे	0.12	क्रियान्वयन सहायता
4.	प्रशिक्षण एवं क्षमता-आईएएस का निर्माण	प्रति वर्ष 200,000 रुपये की एकमुश्त राशि	0.20	क्रियान्वयन सहायता
5.	कार्यान्वयन/निगरानी दौरे	प्रति माह 2 दौरे, प्रति दौरे 5,000 रुपये	0.12	क्रियान्वयन सहायता
6.	बाहरी निगरानी और E1 तथा S1 परियोजनाओं का मूल्यांकन	प्रति वर्ष 1 परियोजना, प्रति परियोजना 500,000 रुपये की एकमुश्त राशि	0.50	क्रियान्वयन सहायता
7.	बाहरी ईएसएमएस ऑडिट	प्रति वर्ष 1 ऑडिट, 1,000,000 रुपये की एकमुश्त राशि	1.00	क्रियान्वयन सहायता
		कुल:	**4.30**	